RNI NO. CHHHIN/2022/83778

न्यूज रूटीन

जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं!

मासिक, बलौदाबाजार से प्रकाशित

वर्ष : 03 अंक : 05 | मासिक, बलौदाबाजार, मई 2024 | E-mail: newsroutine6@gmail.com | पृष्ठ : 16 | मूल्य : 15 रू.

कांग्रेस द्वारा पैदा किए भरोसे के संकट दूर कर विश्वास फिर से बहाली की है- मुख्यमंत्री साय

चुनावों में लगातार कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री को गाली देना ,गृह मंत्री का वीडियो एडिट करना बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश भर से जिस तरह के फीडबैक आ रहे हैं, लगातार होती रही चुनावी सभाओं में जैसी भीड़ उमड़ रही थी, जिस तरह माताओं-बहनों का स्नेह दिख रहा था, उससे वे इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी की पूरी ग्यारह सीटें जीत कर विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी इतिहास बनाएगी।

साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर इस बार अनेक देशों के प्रतिनिधि और नेता भारत आए, उनका छत्तीसगढ़ भी आगमन हुआ, वे काफी कुछ यहाँ से प्रेरणा लेकर अपने देश गए हैं। यह भी इस चुनाव की विशेषता रही। साय ने कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा कर देने के लिए हमारे पास जहां एक बड़ा विजन है। जहां हम अपनी योजनाओं, रोडमैप और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच थे, वहीं देश भर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने नकारात्मकता और दुष्प्रचार, बदजुबानी की सारी सीमाएं लांघ दी। विशेषकर अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जहां की तासीर के बारे में सारा देश जानता है, जो सभ्यता और संस्कृति के लिए देश-दुनिया में प्रशंसित है। वहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरह का झूठ, दुष्प्रचार और शालीनता की सीमा पार की, उसे किसी भी सभ्य

समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विश्व के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरह की भाषा विपक्ष ने इस्तेमाल की है, उससे हम शर्मिंदा हुए हैं। यह बिल्कुल ही अस्वीकार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर हमारा विजन पूरी तरह स्पष्ट है। हमने राजनीति में शुचिता और विश्वास का वातावरण बहाल किया है। पिछले सौ दिन में हमने कांग्रेस द्वारा पैदा किए भरोसे के संकट को दूर कर विश्वास की फिर से बहाली की है, निस्संदेह हमें तीसरे चरण में भी जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिलने जा रहा है। दोनों चरण के जो फीडबैक हमारे पास आए हैं, वह भी उत्साहजनक हैं। उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस भीषण गर्मी में भी लगातार कवरेज कर रहे मीडिया के मित्रों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन ने विश्वास करते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा को जिताया और भाजपा की सरकार बनाई है। प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि चार महीनों की अल्पावधि में मोदी की गारंटी को पूरा करने में उनकी सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार बनने के बाद पहला काम प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे कांग्रेस की सरकार ने रोक रखा था, उसकी स्वीकृति पहली कैबिनेट बैठक में दे दी गई। 2 वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान 25 दिसंबर को कर दिया गया। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की शुरुआत भाजपा ने की और रिकॉर्ड खरीदी की। इस वर्ष 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया और अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान 12 मार्च को 24.72 लाख किसानों के खातों में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त भी अंतरित की जा चुकी है। रामलला दर्शन योजना का वादा भी पूरा कर दिया गया है। पीएससी घोटाला की जाँच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। वनवासी भाइयों से तेंदूपत्ता की खरीदी 5,500 रु. प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी करने की घोषणा हमने कर दी है।

छत्तीसगढ़ पूरी तरह मोदीमय है - किरण सिंह देव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद द्वितीय चरण में तीन लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न हुए। छत्तीसगढ़ के चार लोकसभा क्षेत्रो का चुनाव संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों का 7 मई को तृतीय चरण में मतदान संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ में हुए सभी चरणों के मतदान में हमारे राष्ट्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ आना हुआ है जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं का चुनाव प्रचार में आना हुआ है, जिससे लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए भाजपा के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन का आभार माना है। श्री देव ने कहा छत्तीसगढ़ में वातावरण पूरी तरह मोदीमय है। हम 11 की 11 सीटे जीत रहे है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव,विधायक मोतीलाल साहू, खुशवंत साहेब, रायपुर लोकसभा प्रभारी संदीप शर्मा, प्रवक्ता केदार गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, सहप्रभारी अनुराग अग्रवाल भी मौजूद थे।

प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन वहीं रोशनी को तरसे ग्रामीण

करतला। प्राकृतिक ससांधन से भरपूर कोरबा जिला विकास की मुख्यधारा से दूर है। अलग-अलग विकासखंडों में आज भी कई ऐसे गांव है, जहां के लोगों ने कभी बिजली नहीं देखी है। विकास क्या होता है? यह नहीं जाना है। यह हाल तब है जब प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कोरबा में ही होता है।

इन लोगों तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच सकी है। एक ऐसा ही गांव है कोरबा जिले के विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत स्थित गांव बुरनीझरिया। इस गांव में उरांव और पंडो जनजाति के लोग रहते हैं। गांव में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इस अवधि में उनके गांव तक कोई सांसद भी नहीं पहुंचा है। गांव के लोगों ने बताया कि पिछली सरकार में क्षेत्र के विधायक पहली बार उनकी गांव आए थे।

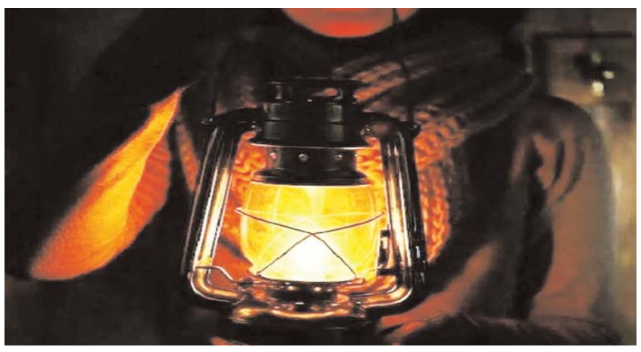

गांव के लोगों ने विधायक से बिजली की मांग की थी। विधायक ने आश्वासन दिया था, कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर गंभीर है। जल्द ही उनके गांव में बिजली पहुंच जाएगी। इस बीच विधायक के पांच साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया। मगर उनके गांव तक बिजली नहीं पहुंची। अब ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय जब लोकसभा का चुनाव संपन्न होने वाला है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में आज तक कोई सांसद भी नहीं पहुंचा है। चाहे वह किसी भी पार्टी का हो।

विद्युतीकरण के नाम पर करोड़ों खर्च

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से प्रदेश सरकार ने कई कोशिशें की। इसमें केंद्र सरकार से भी मदद मिली। लेकिन इसका लाभ पूरी तरह आदिवासी बाहुल्य इलाके में नहीं पहुंचा। आज भी कोरबा जिले में कई गांव है। जहां बिजली नहीं है। इसमें कोरबा जिला मुख्यालय से कोसों दूर स्थित ग्राम बगदरीडांड भी शामिल है। संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा के गांव सरडीह को भी बिजली और प्रदेश सरकार की योजनाओं का इंतजार है।

छत्तीसगढ़ में क्या टूटेगा 9-2-11 फॉर्मूला

अनूप दत्ता

शायद यह महज इत्तेफाक हो कि 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद संपन्न हुए चार लोकसभा चुनावों में यहां की 11 लोकसभा सीटों पर हमेशा भाजपा का ही पलड़ा भारी रहा है। 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हारती रही, या उसे एकाध सीटें ही मिलीं। लगातार 15 वर्षों तक भाजपा इस राज्य से 10 सांसदों को भेजने में कामयाब रही। इन चार चुनावों में कांग्रेस के कई दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी, श्यामाचरण शुक्ल, पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और बस्तर टाइगर कहे जाने वाले दिवंगत महेंद्र कर्मा शामिल रहे।

पहले लोकसभा चुनाव यानी 2004 में सिर्फ अजित जोगी ही कांग्रेस से जीत पाए थे। तब भाजपा में शामिल हुए विद्याचरण शुक्ल की महासमुंद सीट पर जोगी के हाथों हार हुई थी। उसके बाद विद्याचरण दोबारा कांग्रेस में चले गए। कर्मा और विद्याचरण 25 मई 2013 को दरभा घाटी में हुए नक्सली हमले में मारे गए।

भाजपा की हैट्रिक पर 15 वर्षों बाद जाकर रोक लगी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दो सीटें पाने में सफल रही। 2004 से 2019 के बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के मत प्रतिशत में बढ़ोतरी जरूर हुई पर कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ नहीं मिल सका। भाजपा के वोट लगभग 6 फीसदी बढ़े और कांग्रेस के 4 फीसदी। तो इससे क्या यह समझा जाए कि इस बार भी भाजपा का पलड़ा कांग्रेस पर भारी रहेगा या फिर तिलिस्म टूटने जा रहा है?

2019 के लोकसभा चुनाव में पड़े 71.49 प्रतिशत वोट

2019 के चुनाव में रायगढ़ लोकसभा सीट पर सबसे अधिक 77.78 प्रतिशत और सबसे कम बिलासपुर लोकसभा सीट पर 64.36 वोट प्रतिशत था

तीन महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया था। कांग्रेस का वोट शेयर लुढ़क गया और उसने आदिवासी बहुल सीटें हाथ से खो दीं। चुनाव में राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में भाजपा को 54 और कांग्रेस को 35 सीटें मिलीं। भाजपा का वोट शेयर 33 फीसदी से बढ़कर 46.27 फीसदी हो गया।

विधानसभा चुनावों की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी भाजपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के मामले में कांग्रेस से आगे है। वह सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इनमें तीन महिलाएं हैं– महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, कोरबा से सरोज पांडे और जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े। कांग्रेस छह सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दो पूर्व राज्य मंत्रियों और एक मौजूदा सांसद को मौका दिया गया है।

विधानसभा चुनावों की तर्ज पर भाजपा इस बार भी भ्रष्टाचार के मुद्दों को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की शुरुआत कर चुकी है। महादेव सट्टा ऐप का जिन्न फिर से बाहर आ गया है। आर्थिक अपराध शाखा की एफआइआर में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का नाम आने के बाद भाजपा उन्हें घेरने में लगी है। कांग्रेस को महंगाई समेत अन्य मुद्दों का सहारा है। पार्टी किसानों की दयनीय स्थिति और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी भाजपा पर निशाना साध रही है। भाजपा के पिछले महीनों का राज भी कांग्रेस के लिए एक मुद्दा है, हालांकि लोकसभा चुनाव में पिछले दो बार की तरह इस बार भी भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का ही बड़ा सहारा है।

छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान

4 जून को नतीजे

- 19 अप्रैल को एक सीट
- 26 अप्रैल को 3 सीट
- 7 मई को सात सीट

लोकसभा में दलगत स्थितियां

		भाजपा	कांग्रेस
2019	सीट	9	2
	वोट प्रतिशत	50.70%	40.91%
2014	सीट	10	1
	वोट प्रतिशत	49.7%	39.1%
2009	सीट	9	1
	वोट प्रतिशत	45.03%	37.31%

सरकार के तीन माह के कार्यकाल में राज्य में लौटी खुशहाली

कोरबा। प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव सरकार के 100 दिन पूरे होने पर श्रम एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि बीते पांच साल में कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी से हर वर्ग में असंतोष का माहौल था, भाजपा सरकार के इन तीन माह में ही आम जनता के बीच खुशहाली लौटी है। विष्णुदेव सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को इन 100 दिन में ही पूरा किया है।

मंत्री देवांगन ने कहा कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल, महतारी वंदन योजना, 18 लाख पीएम आवास योजना की सौगात जनता को मिल चुकी है। जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य विभागों के माध्यम से भी योजना का लाभ लोगों को मिलने लगी है। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री देवांगन ने कहा कि कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा की जीत पक्की है। सरोज पूरे छत्तीसगढ़ की बेटी है, उनके जैसा सशक्त नेतृत्व कोरबा को मिलने वाला है। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर, भाजपा जिलाध्यक्ष डा राजीव सिंह, बिहार से आए एमएलसी देवेश, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम हितानंद अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, सह प्रभारी पवन सिन्हा समेत भाजपा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जयसिंह को भाजपा में लेने का सवाल नहीं उठता

नेता प्रतिपक्ष डा चरण दास महंत द्वारा पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भाजपा में शामिल करने के लिए दबाव बनाए जाने के सवाल पर मंत्री देवांगन ने कहा कि वे कई तरह के आरोप में घिरे हुए हैं। उन्हें लेने का सवाल ही नहीं उठता है। हार को देखते हुए अब कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, सब को पता है कि इस चुनाव में कांग्रेस की नैया पूरी तरह से डूब जाएगी।

डीएमएफ में हो रही थी अनियमितता तो सांसद क्यों थी मौन

नगर निगम के श्यामनगर और इंदिरानगर में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री देवांगन ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत बीते पांच साल से संसदीय क्षेत्र से गायब रही और जनता ने उन्हें देखा ही नहीं। कोरबा में डीएमएफ में अरबों का घोटाला हुआ और सांसद ने कभी विरोध नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि ज्योत्सना महंत की भी सहमति थी।

नवलपुर में नए सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति शुरू

लोरमी। विकासखंड के ग्राम नवलपुर में नए सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई है। भाजपा के पदाधिकारी गुरमीत सलूजा , धनीराम यादव, प्रदीप मिश्रा,रवि शर्मा , ज्ञानेश्वर क्षत्रिय, दरबारी यादव ने सब स्टेशन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विभाग के अधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद थे।

लोरमी विकासखंड में गर्मी में धान की फसल एवं निस्तारी के लिए खुड़िया बांध से पानी छोड़े की मांग की जा रही है। इस परिपेक्ष में जिला महामंत्री गुरमीत सलूजा, रवि शर्मा, रामेश्वर बंजारे, जवाहर दिवाकर एवं अन्य पदाधिकारी ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन देकर एवं डिप्टी सीएम से चर्चा कर शीघ्र ही खुड़िया बांध से पानी छोड़े जाने की मांग की। महामंत्री गुरमीत सलूजा ने बताया कि उपमुख्यमंत्री से चर्चा हो गई है। अति शीघ्र ही गर्मी में धान की फसल के लिए पानी दिया जाएगा।

कांग्रेस ने दी न्याय की 5 गारंटी, हर साल महिलाओं को मिलेगा 1 लाख रुपये, सरकारी भर्ती में मिलेगा लाभ

रायपुर। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां जोर-शोर से हो रही है. वहीं राजधानी रायपुर में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज कांग्रेस ने पत्रकारवार्ता ली. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 न्याय की गारंटी लोगों दी गई है. कांग्रेस ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपये मिलेगा. भाजपा सरकार महिलाओं को 1000 रुपये देती है, लेकिन कांग्रेस 8333 रुपये प्रति माह देगी. इसके अलावा केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये मजदूरी मिलेगी. वहीं एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी.

पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों 5 न्याय की गारंटी दी है. कांग्रेस का मानना है देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले. इसके लिए पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है.

जानिए कांग्रेस की 5 गारंटियां कौन-कौन सी है

नारी न्याय में कांग्रेस महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी. इसमें हर महिला को साल में एक लाख रुपये यानी महिने में 8333 रुपये मिलेंगे. भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महिने में मात्र 1000 रुपये यानी साल में 12,000 रुपये देगी. मगर कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी.

कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी.

आशावर्कर, आंगनबाड़ी और मिडडे मील कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जाएगा.

महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी.

देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल बनाया जाएगा.

किसान न्याय में कांग्रेस किसानों के सुख-समृद्धि के लिए 5 गारंटी देती है.

एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा. इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा. डॉ. एमएस स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी.

किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी.

किसानों के फसलों के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से डिजाइन किया जाएगा.

कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी. यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा.

किसान जीएसटी मुक्त होंगे. कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छुट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा.

युवा न्याय में कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिए युवाओं को 5 गारंटी देती है.

भर्ती भरोसा- केन्द्र सरकार में कैलेंडर के नुसार 30 लाख नयी नौकरियां।

पहली नौकरी पक्की- प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रू (8500/ माह)

पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिये एक नीति

गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकॉनामी में युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन युवा रोशनी 5000 करोड़ रू का युवाओं के लिये स्टार्ट- अप कोष

श्रमिक न्याय में कांग्रेस देश के श्रमिकों से वायदा करती है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिए मनरेगा कानून बनाया था और हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया है. अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रुपये करने की गारंटी देती है. इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा.

अवैध मुरूम उत्खनन में लगे 2 चैन माउंटेन और 3 हाइवा जब्त

रायपुर। गोबरा नवापारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोरभट्ठी में राजस्व विभाग ने एसडीएम रवि सिंह के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की. इस दौरान अवैध मुरूम उत्खनन में संलग्न 2 चैन माउंटेन मशीन और 3 हाइवा को जब्त किया है. कार्रवाई के बाद मुरूम का अवैध उत्खनन करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है.

एसडीएम सिंह ने बताया कि उन्हें गांव में अवैध मुरूम उत्खनन की शिकायत मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तो खसरा नंबर 128 में अवैध मुरूम उत्खनन होता पाया गया. पूछताछ में उत्खनन कर रहे लोगों के पास फिलहाल कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला. इसके बाद अवैध मुरूम उत्खनन में लगे 2 चैन माउंटेन और 3 हाइवा को जब्त किया गया है. कार्वाई के दौरान गोबरा नवापारा तहसीलदार सूरज बंछोर, नायब तहसीलदार आलोक वर्मा, राजस्व निरीक्षक, पटवारी आदि लोग उपस्थित थे. राजस्व विभाग की कार्रवाई से जिला खनिज विभाग की कथित सक्रियता की पोल भी खुल गई.

जानकारी के अनुसार, पिछले 15 दिनों से 24 घंटे बेतहाशा मुरूम का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था. इसके बावजूद खनिज विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी या यूं कहें कि खनिज विभाग ने जानबूझकर इस ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा.

वहीं इसको लेकर ग्रामवासी तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि ऊपर से कोई दबाव आता है तभी खनिज विभाग कुंभकरणी नींद से जागता है. गांव के कुछ लोगों ने बताया कि मुरूम का उपयोग भारतमाला परियोजना में किया जा रहा था, जो कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी परियोजना है.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 410 कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल

पामगढ़। जिला जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी में लोक सभा चुनाव के दौरान इस्तीफों का सिलसिला थम नहीं रहा है। लोक सभा क्षेत्र जांजगीर चांपा के चुनाव से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। गत दिनों कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। ग्राम पंचायत पामगढ़ से सरपंच तेरस राम यादव, ब्लाक कांग्रेस के महामंत्री प्रदीप बनर्जी, पूर्व जनपद पंचायत पामगढ़ के अध्यक्ष डमरू मनहर, शिवरात्रि गुप्ता, संतोषी मनोज रात्रे सहित अन्य लोगों ने कांग्रेस को छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष व्यास वर्मा ने बताया कि आरंग विधान सभा क्षेत्र के प्रथम युवा विधायक गुरू खुशवंत साहेब के उपस्थिति में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 410 कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कार्यकताओं ने भाजपा की दामन थाम लिया हैं।

बीते कुछ दिनों से कई कांग्रेसियों ने पार्टी से नाता तोड़ कर भाजपा का दामन थामा है। गुरू खुशवंत साहेब ने भाजपा का गमछा पहना कर पार्टी में शामिल किया। ज्ञात हो कि इसके पूर्व पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र से माटी कला बोर्ड की सदस्य रही पुनिता प्रजापति भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो हुई है। शेषराज हरबंश पामगढ़ में कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक हैं वे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र से बाहरी प्रत्याशी हो कर यहां से पहली बार चुनाव जीत कर कांग्रेस पार्टी के पामगढ़ से विजयी प्रथम महिला विधायक के रूप में अपनी नाम दर्ज कर ली है। क्षेत्र की कांग्रेस की दिग्गज कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर नहीं चल रहीं थीं, जिसके कारण नाराज कार्यकर्ताओं ने लोक सभा चुनाव आते ही भाजपा का दामन थाम ली है। आगे भी कई कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ताओं की भाजपा में शामिल होने की सिलसिला चल रहा है।

संपादकीय

स्वार्थ से प्रेरित है भारत विरोधी प्रचार

पश्चिमी सरकारों, संस्थानों और मीडिया द्वारा भारत विरोधी नैरेटिव बनाने की कोशिश के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो बयान आया है, वह पूरी तरह सही है। भारत के विकास तथा उसके वैश्विक प्रभाव को बाधित करने की मंशा से कुछ देश हमारे विरुद्ध तरह-तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा केवल सरकारों की ओर से नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें मीडिया और संगठनों की भूमिका भी है। उदाहरण के तौर पर, जॉर्ज सोरोस और उनके फाउंडेशन की ओर से खुले रूप से देश में सरकार बदलने की बातें कही गयी हैं। इस तरह के अनावश्यक हस्तक्षेप और दबाव बनाने की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, पर देश में चुनावी सरगर्मी शुरू होने के साथ इसमें तेजी आयी है। पश्चिमी सरकारों और मीडिया ने निज्जर और पन्नू के मामलों में भारतीय एजेंसियों के शामिल होने की निराधार बातें की, मानवाधिकार को लेकर सवाल उठाने के प्रयास हुए। आंतरिक राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था के बारे में टिप्पणियां भी की गईं। इसे लेकर भारत सरकार की ओर से कड़ा एतराज दर्ज कराया गया है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह सब एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। एक प्रकार से यह उनका विशेष टूल-किट है, जिसे वे अपनी मीडिया के जरिये बढ़ाना चाहते हैं।

इसी क्रम में पश्चिम के कई देशों ने अपनी संस्थाएं स्थापित की हुई हैं, जिन्हें वे शोध संस्थान और नागरिक समाज की श्रेणी में रखते हैं। ये समूह तथ्यों को तोड़-मरोड़कर तथा पूर्वाग्रह से ग्रस्त अपने विश्लेषण को बिल्कुल पेशेवर अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा वे इसलिए कर पाते हैं कि उनके पास एक मजबूत मीडिया है। अनेक देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, का मीडिया कई मामलों में पश्चिम की अंग्रेजी मीडिया पर निर्भर और उससे प्रभावित रहता है। जानकारी के अभाव में या उनके प्रभाव में भारत में भी मीडिया कई बार पश्चिम मीडिया की बातों को दोहराता रहता है।

जल-संकट चुनाव जीतने का नहीं, समाधान का माध्यम बने

वास्तव में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके गंभीर परिणामों के चलते राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है।

देश के कई भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जैसे-जैसे गर्मी प्रचंड होती जा रही है, जल संकट की खबरें भी डराने लगी है। राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक आदि प्रांतों में पानी के लिये त्राहि-त्राहि मची है। मध्यप्रदेश के छतरपुर ज़िले महर-खुवा गांव में जल-संकट की तस्वीरें भयावह एवं डराने वाली है। इस गांव में लगभग 100 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनके पास अब इतना भी पानी नहीं बचा है कि ये दिन में दो वक्त का खाना बना सकें और अपनी प्यास बुझा सकें। ऐसे हजारों गांव हैं, जहां पानी के अभाव में जीवन संकट में हैं। भारत अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। लोकसभा चुनाव अन्तिम चरण की ओर अग्रसर है, आज हमारे उम्मीदवार मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा करके चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन भारत में जिस तरह पानी का संकट गंभीर हो रहा है, उससे उनकी कथनी और करनी की असमानता ही बार-बार उजागर होती है। जल-संकट चरम पराकाष्ठा पर है, एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब पैसा देकर भी पानी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। जल-संकट चुनाव जीतने एवं राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा तो है, लेकिन समाधान का नहीं। जल संकट ने राजनीतिक रंग तो ले लिया है, विभिन्न राजनीतिक दल एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं और पिस रहा आम आदमी। पैसे वालों के लिए पानी इतनी बड़ी समस्या नहीं है लेकिन जिन लोगों के पास पैसों की किल्लत है, वे पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं क्योंकि टैंकर का पानी महंगा पड़ रहा है। वास्तव में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके गंभीर परिणामों के चलते राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। देश का आईटी हब बेंगलुरु गंभीर जल संकट से दो-चार है। जिसका असर न केवल कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते जल संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई चिंताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं। देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी की उनकी भंडारण क्षमता के अनुपात में तीस प्रतिशत की गिरावट आई है। जो हाल के वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट है। जो सूखे जैसी स्थिति की ओर इशारा करती है। महर-खुवा गांव की ही तरह अलवर जिले के कई गांव में लोग किसी एक मौसम में नहीं, बल्कि 12 महीनें भीषण जल संकट का सामना कर रहें है। इन गांवो में पानी का स्त्रोत है ही नहीं। इन इलाकों में पानी की इतनी कमी है कि लोग उसे अपने घरों में टैंकर में छिपाकर और ताला लगाकर सुरक्षित रखने लगे हैं। भारत के गांवों में रहने वाले करीब 20 करोड़ परिवारों के घरों में नल नहीं है। इन परिवारों की औरतें पैदल चलकर, घंटों लाइन में लगकर पानी इकट्ठा करती हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार ने साल 2019 में हर घर में नल से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की। सरकार का दावा है कि अब तक 10 करोड़ घरों में नल लग गए हैं। लेकिन अभी हजारों गांवों में जल-संकट एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एक नागरिक के रूप में हम आत्ममंथन करें कि बढ़ते जल-संकट के समाधान की दिशा में हमने क्या कदम उठाये। क्या पानी की फिजूल खर्ची को कम करने का कोई संकल्प लिया? गर्मी के आने पर हम हाय-हाय तो करने लगते हैं, लेकिन कभी हमने विचार किया कि हम इस स्थिति को दूर करने के लिये क्या योगदान देते हैं? क्या हम पौधा-रोपण की ईमानदार कोशिश करते हैं? हम जल के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करते हैं? क्या वर्षा जल सहेजने का प्रयास करते हैं ताकि तापमान कम करने व भूगर्भीय जल के संरक्षण में मदद मिले? सच कहें तो हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के अनुरूप जैसी जीवन शैली विकसित की थी, वह हमें कुदरत के चरम से बचाती थी। राजस्थान में जल-संकट की संभावनाओं को देखते हुए आम नागरिक खुद के स्तर पर व्यापक प्रयत्न करता है। रेगिस्तान से जुड़े अनेक गांवों एवं शहरों में बने या बनने वाले मकानों में कुआ जरूर होता है, जहां बरसात के पानी को एकत्र किया जाता है, जो संकट के समय काम आता है। इसलिये गाँव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत करनी चाहिये। उचित रख-रखाव के साथ छोटे या बड़े तालाबों को बनाने के द्वारा बरसात के पानी को बचाया जा सकता है। हम महसूस करें कि बढ़ती जनसंख्या का संसाधनों में बढ़ता दबाव भी तापमान की वृद्धि एवं जल-संकट का कारण है।

ममता सरकार संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर नहीं

पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार देश में एकमात्र ऐसी सत्तारुढ़ पार्टी बन गई है जिसका देश के संविधान और न्यायपालिका में भरोसा नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शगल बन गया है। ममता को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नजर आती है, इसके लिए बेशक कानून की कितनी ही धज्जियां क्यों न उड़ानी पड़ी। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रोहिंग्या मुसलामानों के अवैध प्रवेश का हो या फिर बांग्लादेशियों का। इसके लिए ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों पर भी केंद्र की भाजपा सरकार की खिलाफत की है। कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के हाइकमान ने भी कभी ऐसे आरोप केंद्र की भाजपा सरकार पर नहीं लगाए, जैसे कि ममता बनर्जी लगाती रही हैं। ममता ने भ्रष्टाचार, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, राजनीतिक आधार पर बंदरबाट जैसे मुद्दों पर अदालतों से जितनी फटकार खाई है, उतनी देश के किसी राजनीतिक दल की सरकार ने नहीं खाई। इतना सब कुछ होने के बावजूद ममता बनर्जी अपनी आदतों से बाज नहीं आई हैं। नया मामला पश्चिमी बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को अदालत द्वारा रद्द करने का है। इस आदेश को सदाशयता से मान कर अपील करने की दलील देने के बजाए मुख्यमंत्री ममता ने ही फैसला देने वाले हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर भाजपा समर्थक होने का आरोप लगा दिया। ऐसा करके ममता ने बगैर किसी भय के सरेआम अदालत की अवमानना कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी, जो तपशिली समुदाय को दिए गए अधिकार छीन लेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस प्रशासन के तहत 2011 से बंगाल में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रमाणपत्रों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, हालांकि, इससे वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी या सीटें रखने वाले या जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दाखिल करने वाले लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। उस रिपोर्ट में देश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में विस्तृत बातें की गई थीं। रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों में केवल 3.5 फीसदी ही मुस्लिम थे। इसी को आधार बनाकर 2010 में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने 53 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण सात फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। इस तरह उस वक्त करीब 87.1 फीसदी मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन, 2011 में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसका यह फैसला कानून नहीं बन सका। फिर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं। ममता की सरकार ने इस सूची को बढ़ाकर 77 कर दिया। 35 नई जातियों को इस सूची में जोड़ा गया, जिसमें से 33 मुस्लिम समुदाय की जातियां थीं। साथ ही तृणमूल सरकार ने भी राज्य में ओबीसी आरक्षण सात फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक

लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की दी जानकारी

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

बैठक में बताया गया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक यह प्रभावशील रहेगी। राज्य में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी सतत अद्यतीकरण में मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है। राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे-रैंप, पेयजल, विद्युत प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है। प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाता सहायता केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि सभी मतदान केन्द्रों में बुजुर्गजनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु मतदाता मित्र आवश्यक सहयोग हेतु उपस्थित रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं कोविड-19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्रारूप के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे।

बैठक में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा तथा व्यय लेखों के संधारण के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। बैठक में निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस. ध्रुव सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

विधायक कविता प्राण लहरे के नेतृत्व में सचिन पायलट का भव्य स्वागत

बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का गिधौरी में विधायक कविता प्राण लहरे के नेतृत्व में जोरदार आत्मीय स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर से जांजगीर चांपा प्रवास पर है। इस दरमियान दोपहर गिधौरी में बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार आत्मीय स्वागत किया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, जांजगीर चांपा लोकसभा प्रत्याशी डॉ. शिवकुमार डहरिया व कई शीर्ष नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया, सैकड़ों के तादात में उपस्थित कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था एवं सभी कार्यकर्ताओं ने अपने शीर्ष नेताओं के साथ जांजगीर के लिए रवाना हो गए। विधायक कविता प्राण लहरे ब्लॉक अध्यक्ष युधिष्ठिर नायक, दीपक टंडन, लव साहू, नेमीचंद केसरवानी, छत्रसाल साहू, असारत खान, इंदु पडवार, शेख अलीमुद्दीन,शंकर नारंग, एफ एल खटकर, हरनारायण साहू, संतोष देवांगन, धर्म वर्मा मोती साहू ,दिनेश देवांगन, भुरवा सिंह गौड़ आदि उपस्थित थे।

सीएचसी में अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्स-रे जैसी सुविधाएं बंद

पथरिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में शासन की ओर सुविधा बढ़ाने अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्स-रे जैसी मशीनें दी गई हैं किंतु आपरेटर नहीं होने से बेकार है। व्यवस्था सुधारने को लेकर अधिकारी भी गंभीर नहीं है परिणाम स्वरूप शासन की योजना के लाभ से वंचित हैं।

विकासखंड पथरिया मरीज के सुविधाओं के लिए सहायक उपकरण तो हैं किंतु आपरेटर नहीं होने से धूल खाते पड़े हुए हैं। ज्ञात हो कि क्षेत्र में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं छह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन मुख्यालय से किया जा है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में तीन चिकित्सक पदस्थ हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमोरा लौदा, भटगांव आदि में भी चिकित्सक भी पदस्थ किए गए हैं। समय-समय पर क्षेत्र के डाक्टरों की भी सेवाएं ली जाती हैं। इनमें तीन महिला डाक्टर भी हैं। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 25 से 30 किलोमीटर क्षेत्र के लोग उपचार के लिए आते हैं। अधिकतर मामले दुर्घटना के होते हैं इसके बाद भीएक्स-रे की सुविधा नहीं मिल पाती है इससे घायल मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है और उन्हें जिला चिकित्सालय भेज दिया जाता है। पीड़ित ने बताया कि एक्स-रे के लिए यहां टेक्नीशियन के लिए सिर्फ शुक्रवार का दिन निर्धारित है यानी की बाकी के दिन बाहर में सुविधा लेने को कहा जाता है।

परिवार नियोजन में हो रही है असुविधा ॰ लोगों ने बताया कि परिवार नियोजन जैस कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिन निर्धारित किए गए हैं लेकिन संख्या कम निर्धारित होने से अधिकतर महिलाओं को लौटना पड़ता है। पथरिया मुख्यालय में दस महिलाओं का पंजीयन किया जाता है दूर दराज से आई महिलाओं को सुविधा नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पतालों में शरण लेनी पड़ती है।

लोगों की सुविधा का रखेंगे ख्याल -बंजारे

बीएमओ डा अनुज राम बंजारे ने पीएचसी में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा लोगों की सुविधा का ख्याल रखेंगे। गर्मी के दिनों में बचाव के लिए ओआएस अन्य दवाएं उपलब्ध हैं। टीकाकरण समय-समय पर होने से किसी तरह की बीमारी से बचाव के लिए दवा उपलब्ध है।

स्कूल में नियमों को ताक में रखकर काटे गए पेड़

पेंड्रा । स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम हाईस्कूल में नियमों को ताक में रखकर नीलगिरी के पेड़ों को कटवाने की जानकारी मिलने पर नगर के जनप्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने कटाई रूकवा दिया।

ज्ञात हो स्कूल परिसर में वर्षों से नीलगिरी के पेड़ लगे हुए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल एलपी डाहिरे स्कूल में फ्राइडे की छुट्टी होने पर पेड़ कटवा रहे थे। सुबह मामले की जानकारी लगते ही पेंड्रा के जनप्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जालान, पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह, भाजपा नेता एवं पार्षद राकेश चतुर्वेदी, मनीष श्रीवास और पूर्व छात्र स्कूल पहुंच गए। उन्होंने पेड़ों की कटाई को रुकवा दिया। पेड़ काटने वाले व्यक्ति रोहित राम चौधरी ने बताया कि उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से चार हजार रुपए प्रति

पेड़ के हिसाब से पेड़ काटने की बात की है, और इसी हिसाब से उन्होंने प्रिंसिपल को भुगतान भी कर दिया है, और प्रिंसिपल के कहने पर ही पेड़ काट रहे हैं। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पेड़ नहीं कटवाया है।

एसडीएम पेंड्रारोड के आदेश से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल परिसर में जीर्ण शीर्ण हो चुके नीलगिरी के पेड़ काटे जा रहे हैं। मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि एसडीएम ने स्कूल परिसर में लगे जीर्ण शीर्ण पेंड़ों को वन विभाग को काटने का आदेश दिया था , लेकिन प्रिंसिपल एलपी डाहिरे ने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के निजी व्यक्ति द्वारा पुराने पेड़ों के साथ ही हरे भरे पेड़ों को भी कटवा दिए। हालांकि प्राचार्य एलपी डाहिरे ने सभी आरोपों से इनकार किया है। मामले में नपा अध्यक्ष ने हरे भरे पेंड़ों को नहीं काटे जाने की बात कही। उन्होंने कहा एक पेड़ को विशाल वृक्ष बनाने में काफी समय लगता है ऐसे में पेड़ों को नहीं काटना चाहिए।

चाय बेचने वाला, साधारण किसान भी बन सकता है मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री, ये भाजपा में ही संभव-साय

कोण्डागांव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडागांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए. सभा को संबोधित करते हुए साय ने कहा, मैं दूसरी बार यहां आया हूं. पहले जंगल जात्रा में आया था. 5500 रुपए तेंदूपता का देने की घोषणा कोंडागांव से की थी. आज 90 विधानसभा में बूथ विजय का अभियान शरू कर दिया है. कार्यकर्ता घर-घर में भाजपा का ध्वज लगाएं. 19 अप्रैल को आपको सांसद चुनना है. विधानसभा का चुनाव भारी मतों से जीते हैं. एक इंजन ठीक हो गया. अब दिल्ली के इंजन को आगे बढ़ाना है. 140 करोड़ लोगों का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है. तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है. ये हर कार्यकर्ता की जावबदेही है.

सीएम साय ने कहा, डबल इंजन में ही विकास तेजी से होगा. आप सबसे आग्रह है कि सभी अपने को महेश कश्यप मानें. प्रत्याशी हर घर, गांव नहीं पहुंच पाता इसलिए आपको महेश कश्यप, मोदी की गारंटी पर भरोसा सबको दिलाना है. आज लोग तीन माह के काम से ताज्जुब कर रहे. 18 लाख मकान बनने शरू हो गए हैं. दो साल का बकाया बोनस दिया है. 5 साल में बोनस कांग्रेस को याद नहीं आई. हमने सत्ता में आते ही 12 लाख किसानों को बोनस दिया. महतारी वंदन योजना हमने शरू कर दी है. ये है मोदी की गारंटी. 2 या 3 अप्रैल को फिर डल जाएगा. राम भक्तों को सरकारी खर्च पर अयोध्या भेज रहे.

सीएम ने कहा, पीएससी घोटाले भी हमने सीबीआई को सौंप दी है. घोटाला करने वाले नहीं बचेंगे. सभी को जेल जाना होगा. हर चीज में घोटाला किया. आज सबकी जांच कर रहे हैं. सरगुजा, बस्तर का विकास रोक रखा था. कांग्रेस के लिए अदिवासी सिर्फ वोट बैंक हैं. गांव के रहने वाले आदिवासी को आज मुख्यमंत्री बना दिया है. एक चाय बेचने वाले एक साधारण किसान भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है. ये भाजपा में ही संभव है.

बीएसएनएल अगस्त से देशभर में शुरू करेगी 4जी सेवाएं

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल इस साल अगस्त से पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 4जी सेवाएं देशभर में शुरू कर देगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अधिकारियों ने 4जी नेटवर्क पर 40-45 मेगाबिट प्रति सेकंड (एमबीपीएस) की अधिकतम गति दर्ज करने का दावा किया है। इसे पायलट या प्रायोगिक चरण के दौरान 700 मेगाहर्ट्ज के प्रीमियम स्पेक्ट्रम बैंड के साथ 2,100 मेगाहर्ट्ज बैंड में भी पेश किया गया है।

कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और दूरसंचार अनुसंधान संगठन सी-डॉट के नेतृत्व वाले गठजोड़ द्वारा स्वदेशी स्तर पर विकसित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पंजाब में 4जी सेवाएं शुरू की हैं और वह लगभग आठ लाख ग्राहकों को अपने साथ जोड़ चुकी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''सी-डॉट का बनाया हुआ 4जी कोर पंजाब में बीएसएनएल नेटवर्क में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसे पिछले साल जुलाई में स्थापित किया गया था। ऐसी जटिल प्रौद्योगिकी की सफलता साबित करने में 12 महीने लग जाते हैं लेकिन सी-डॉट कोर 10 महीने के भीतर ही स्थिर हो गया है।

इस अधिकारी ने कहा, ''बीएसएनएल अगस्त में पूरे देश में आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी की पेशकश करेगा।%% कोर नेटवर्क एक ऐसा समूह है जिसमें दूरसंचार सेवा से जुड़े नेटवर्क हार्डवेयर, उपकरण और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। टीसीएस, तेजस नेटवर्क और सरकारी स्वामित्व वाली आईटीआई को 4जी नेटवर्क तैनात करने के लिए बीएसएनएल से लगभग 19,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस नेटवर्क को आगे चलकर 5जी में अद्यतन किया जा सकता है। तेजस नेटवर्क के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी अर्नब रॉय ने हाल ही में कहा था कि बीएसएनएल का मोबाइल नेटवर्क विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है।

मदिरा दुकानों के अहातों के लिए मंगाए गए निविदा प्रक्रिया पूर्ण

रायगढ़। जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के परिसर से संलग्न अहातों, जिनमें मदिरा उपभोग की अनुमति लाइसेंस शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी के व्यवस्थापन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मंगाए गए थे, जिन्हे आबकारी विभाग से जारी निर्देशों का पालन करते हुए मतदान तिथि के पश्चात 10 मई 2024 को सृजन सभाकक्ष कलेक्ट्रेट रायगढ़ में खोला गया। जिला रायगढ़ की कुल 36 में से 26 मदिरा दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिनमे से 13 मदिरा दुकानों हेतु कुल 31 आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए । चयन के दिन वास्तविक कार्यवाही का संपादन करने के पूर्व निविदादाताओं को प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रक्रिया को सभी निविदादाताओं की सहूलियत के लिए बड़े परदे पर दिखाया गया। सभी 13 दुकानों के लिए आवेदन की संख्या अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय उच्च बोली वाले निविदादाताओं का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा ह्ढ्ढष्ट के डेटाबेस से किया गया है।

चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निविदादाता को अपने निविदा प्रपत्र में वर्णित जानकारियों के समर्थन में मूल अभिलेखों के साथ दो कार्य दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है। चयनित प्रथम निविदादाता को आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित अग्रिम राजस्व की अदायगी भी चयन के दो कार्य दिवस के भीतर करना है। जिला स्तरीय उपसमिति द्वारा उसी दिन दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दस्तावेज परीक्षण और अग्रिम राजस्व जमा करने में असफल रहने पर चयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा एवं द्वितीय क्रम में चयनित आवेदक को अवसर दिया जाएगा तथा ऐसे असफल चयनित आवेदक द्वारा आवेदन के समय जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राशि को जप्त कर अहाता निर्देश की कंडिका 13.1 अनुसार राज्य में कहीं भी कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से भविष्य में वर्जित कर दिया जायेगा। जिला रायगढ़ की 13 मदिरा दुकानों हेतु निर्धारित रिजर्व प्राइज की तुलना में 266 प्रतिशत अधिक बोली प्राप्त हुई है। प्रक्रिया के दौरान सारंगढ़ जिले की 17 दुकानों हेतु भी कुल 44 पात्र निविदाएं खोली गईं। निविदा प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर रायगढ़, कलेक्टर सारंगढ़, अपर कलेक्टर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी, सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़, जिला आबकारी अधिकारी सारंगढ़ समेत आबकारी विभाग के स्टाफ एवं निविदादाता उपस्थित रहे।

भाखानि में चावल रखने की जगह नहीं, दो हजार राइस मिले बंद होने की कगार पर

रायपुर। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल रखने के लिए जगह नहीं है। केवल उसना चावल ही लिया जा रहा है। गोदामों में जगह नहीं होने पर दो माह से मिलरों से कस्टम मिलिंग का अरवा चावल नहीं लिया जा रहा है। अब तक करीब 47 लाख मिट्रिक टन चावल ही जमा हो पाया है।

फिलहाल राइस मिलों को करीब 41 लाख टन से अधिक फोर्टीफाइड अरवा चावल देना बाकी है। चावल नहीं लेने से 2000 से अधिक राइस मिले बंद होने की कगार पर है। एफ सी आई में चावल जमा करने की यही रफ्तार रही ती डेढ़ वर्ष का समय लग जाएगा।

प्रदेश में इस वर्ष छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों से 145 लाख टन धान खरीदा है । जिसका कस्टम मिलिग का चावल भारतीय खाद्य निगम व नागरिक आपूर्ति निगम को लेना है। जिसमें अरवा 67 एवं उसना 68 प्रतिशत चावल दिया जाना है। जिसमें उसना चावल तो भारतीय खाद्य निगम ले रही है। परंतु अरवा पोर्टिफाइड चावल पिछले दो माह से नहीं लिया जा रहा है। इससे चावल में सुखद आ रही है जिसका खामियाजा राइस मिलर को उठाना पड़ रहा है। प्रत्येक राइस मिल को लाखों का नुकसान हो रहा है। भारतीय खाद्य निगम चावल लेने पर केमिकल टेस्ट करती है। चावल जितना पुराना होता है तो वह चावल केमिकल टेस्ट में फेल हो जाता है। जबकि पूरा धान शासन के उपार्जन केन्द्रों से राइस मिलर नेउठा लिया है। धान उठाने के 15 दिन के अंदर चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा करने का नियम है।

भारतीय खाद्य निगम में अब तक करीब 27 लाख मीट्रिक टन और नान में 20 लाख मीट्रिक टन ही चावल जमा हो पाया है। करीब 40 लाख टन चावल और जमा होना है। पिछले दो माह से भारतीय खाद्य निगम में प्रतिमाह 3 चावल जमा हो रहा है। औसतन हर माह 5 लाख टन चावल जमा होना चाहिए। यदि दीपावली तक चावल जमा करने का टारगेट पूरा करना है तो औसतन 7 लाख टन चावल जमा करना होगा।

लाखों का नुकसान हो रहा -परमानंद

कॉन्फिडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष परमानंद जैन ने बताया किराइस मिलों का अरवा चावल भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ में पिछले दो माह से नहीं ले रहा है जिससे प्रत्येक राइस मिलर को लाखों का नुकसान हो रहा है इसके साथ आने वाले सीजन में कस्टम मिलिंग का कार्य प्रभावित होगा। इस समस्या का निदान शासन प्रशासन को जल्द करना चाहिए।

आलू की आड़ में 19 क्विंटल डोडा की तस्करी

19 लाख के डोडा सहित अन्तर्राज्यीय तस्कर बंदी

महासमुंद। पुलिस को चकमा देने के लिए आलू की बोरियों की आड़ में अफीम पोस्त (डोडा) की तस्करी करते हुए राजस्थान के एक तस्कर को सिंघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1904 किलोग्राम डोडा जब्त किया गया। तस्कर डोडा को क्योंझर (ओड़िशा) से राजस्थान बाड़मेर लेकर जा रहा था। सिंघोड़ा पुलिस ने 8 मई को मुखबिर की सूचना पर बार्डर पर ग्राम रेहटीखोल के पास ओड़िशा से छत्तीसगढ़ की तरफ आ रहे एक ट्रक क्रमांक आरजे 19 जीएच 9947 को रोका। ट्रक में एक व्यक्ति सवार था। उससे पूछताछ करने पर पहले गोलमोल जवाब देने लगा। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने वाहन के डाला में आलू की बोरियों के नीचे अफीम पोस्त (डोडा) रखकर क्योझर ओड़िशा से बाड़मेर राजस्थान लेकर जाना स्वीकार किया।

आरोपी ने अपना नाम जगदीश चौधरी पिता विरमा चौधरी 35 वर्ष इंदिरा आवास खडीन थाना रामसर, जिला बाडमेर राजस्थान बताया। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के डाला में आलू बोरियों के नीचे 1904 किलोग्राम अफीम पोस्त (डोडा) मिला। जिसकी कीमत 19.04 लाख रूपए आंकी गई है। सिंघोड़ा पुलिस ने अफीम पोस्त (डोडा) को जब्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 20 बी नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी के पास से एक मोबाइल और 2500 रूपए नकद जब्त किए गए।

ज्ञातव्य है कि अफीम के फूल को बीच से काटकर इसके अंदर से तरल पदार्थ को निकालकर अफीम पाउडर बनाया जाता है। शेष बचे फूल के हिस्सों को डोडा कहते हैं। इसका उपयोग भी नशे के लिए किया जाता है। ज्यादातर ट्रक चालक इसके मिश्रण को तैयार रखते हैं। पंजाब और राजस्थान में इसे खपाया जाता है।

सिंघोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि इस नशीली पदार्थ का ज्यादातर उपयोग ट्रक चालक ही करते हैं। इस नशे का सेवन करने से भूख ज्यादा नहीं लगती है और नींद भी नहीं आती है। ज्यादातर राजस्थान और पंजाब में इसका उपयोग होता है। नशीले पदार्थ को राजस्थान में ही खपने की तैयारी थी।

बलौदाबाजार-भाटापारा का नाम 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में हुआ दर्ज

स्वीप अभियान में बेहतरीन भूमिका निभाने

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के जिले बलौदाबाजार-भाटापारा का नाम लोकसभा चुनाव 2024 मे स्वीप अभियान में बेहतरीन भुमिका निभाने के लिए 5वीं बार 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज हुआ है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को एक साथ दो अवॉर्ड मिले हैं, जिसमें से एक स्वीप आटो जागरूकता अभियान जिसमें 151 आटो चालकों ने कलेक्टर के नेतृत्व में रैली निकाल मतदाताओं से मतदान की अपील की थी। वहीं दूसरा अवॉर्ड स्वीप दीपव घंटी रैली को लेकर मिला, जिसमें मतदाताओं की आरती उतारकर उन्हें मतदान हेतु आमंत्रित किया गया था।

कलेक्टर को सौंपा गया प्रमाण पत्र

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की राज्य प्रतिनिधि सोनल शर्मा ने मतदान दलों की रवानगी से पहले उनकी उपस्थिति में कलेक्टर के.एल. चौहान एवं सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा और बधाई दी।

इस मौके पर कलेक्टर चौहान ने कहा- मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आप सबने मिलकर स्वीप अभियान के तहत बहुत अच्छा काम किया, जिसका परिणाम मिला है कि, हमें आज दो अवार्ड मिले हैं और लोकसभा चुनाव 2024 मे यह पांचवा है जो कि एक रिकार्ड है। उन्होंने रिकॉर्ड बनाने में जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों, मतदाताओं और पत्रकारों के सहयोगिता की बड़ी भूमिका बताई। उन्होंने कहा- मैं सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ साथ ही आप सब बहुत अच्छे से मतदान संपन्न कराये इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

2,000 रुपए के 97 प्रतिशत नोट वापस आए

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि बंद किए गए 2000 रुपए के 97.76 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया कि सिर्फ 7,961 करोड़ रुपए के नोट अभी जनता के पास हैं। आरबीआई ने बयान में कहा कि 19 मई, 2023 को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की गई थी। इस दिन के अंत में बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोटों का मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। अब 30 अप्रैल, 2024 को बाजार में सिर्फ 7,961 करोड़ रुपए के नोट बाजार में हैं।

बैंक ने कहा, इस प्रकार, 2000 रुपए के 97.76 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं हालांकि, 2000 रुपए का नोट वैध है। लोग देशभर में आरबीआई के 19 कार्यालयों पर 2000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं या उन्हें अन्य नोट से बदल सकते हैं। जनता 2000 के नोट भारतीय डाक के माध्यम से भी आरबीआई के किसी भी कार्यालय में भेजकर उनके बराबर मूल्य की राशि अपने बैंक खातों में जमा करा सकती है। आरबीआई द्वारा नवंबर, 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट बंद करने के बाद 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे।

28,200 मोबाइल फोन को ब्लॉक करने का निर्देश

20 लाख कनेक्शनों का भी होगा वेरिफिकेशन

नई दिल्ली। सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, टेलीकॉम कंपनियों से इन हैंडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल नंबरों को फिर से वेरिफाई करने के लिए भी कहा है।

टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 10 मई को जारी एक बयान में कहा कि साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए टेलीकॉम डिपार्डमेंट, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कहा कि इन विभागों के एक साथ काम करने का मकसद धोखेबाजों के नेटवर्क पर रोक लगाना है जिससे कि देश के लोगों को डिजिटल खतरों से बचाया जा सके।

गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि साइबर क्राइम में 28,200 मोबाइल हैंडसेट का गलत इस्तेमाल किया गया था। इसके पता चलने के बाद ही केंद्र सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को 28,200 मोबाइल फोन को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। साथ ही इन हैंडसेट्स से जुड़े 20 लाख मोबाइल नंबरों का फिर से वेरिफिकेशन करने को भी कहा है।

काट दिए जाएंगे कनेक्शन

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के निर्देश दिया है कि अगर इन फोन नंबरों का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उन कनेक्शन को काट दिया जाए। एक आधिकारिक बयान से पता चला है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 7 मई को वित्तीय घोटाले में इस्तेमाल किए फोन नंबर का कनेक्शन काट दिया और उन नंबर से जुड़े 20 मोबाइल फोन को भी ब्लॉक कर दिया था।

पीएम सूर्यघर योजना में छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाएं – आरईसी सीएमडी

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज मुख्यालय में आरईसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) के चेयरमेन-एमडी श्री विवेक कुमार देवांगन ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पीएम-सूर्यघर योजना एवं आरडीएसएस योजना के विभिन्न घटकों के कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि इस योजना को प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। शहरी क्षेत्रों में बने पक्के मकानों की छतों में सोलर पैनल लगाकर लोगों को बिजली उत्पादन के लिए प्रेरित करें, इससे उनके घर का बिजली बिल बहुत कम हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के डंगनिया स्थित मुख्यालय विद्युत सेवा भवन में 6 मई को आयोजित बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के चेयरमेन पी दयानंद ने की। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक द्वय श्री राजेश कुमार शुक्ला एवं श्री एसके कटियार विशेष रूप से उपस्थित थे। देवांगन ने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना, आर.डी.एस.एस का प्रस्तुतिकरण देखा तथा बिंदुवार विषयों की समीक्षा की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन दोनो योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को देश के पाँच अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए गंभीरता से प्रयास करेंगे।

पॉवर कंपनी के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश में 60 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इनमें से 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर हाफ बिजली योजना का लाभ दिया जाता है, उन्हें आधा बिल देना होता है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत यदि वे अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाते हैं तो उनका बिजली बिल और भी कम हो जाएगा, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा। आरईसी के सीएमडी देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हर आवेदक से स्वयं संपर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। उन्हें इस योजना के लिए बैंक से वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करें। उन्होंने वेंडरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि प्रति सौ उपभोक्ताओं के बीच एक वेंडर हो। वेंडर से संपर्क स्थापित कर इस प्रक्रिया को 15 से 20 दिन में पूर्ण कराएं ताकि इस योजना के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर लिया जाए।

देवांगन ने आरडीएसएस योजना के तहत प्रदेशभर में लगने वाले सभी स्मार्ट मीटर की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, वितरण ट्रांसफॉर्मर और फीडर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

श्री देवांगन ने कहा कि स्मार्ट मीटर से पीएम सूर्यघर योजना के लिए अलग से नेट मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रदेश में ऐसी भूमि पर बड़े पैमाने में सोलर परियोजनाएं स्थापित की जाए जहाँ खेती नहीं होती है। वहीं पीएम सूर्यघर योजना के हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिक एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य किया जाए।

सैकड़ों बसपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस प्रवेश

सरायपाली। लोकसभा चुनाव में जांजगीर चांपा सीट के लिए बिलाईगढ़ क्षेत्र की प्रभारी, सरायपाली विधायक चातुरी नंद द्वारा उस क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने ग्राम मोहतरा में आयोजित एक कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गमछा पहनाकर कांग्रेस में प्रवेश कराया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक नंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वंचित शोषित और गरीबों की पार्टी है। उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की गई है, जिससे आज हर वर्ग में उत्साह है।

उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. शिव डहरिया को अपना वोट देकर जिताने की अपील की। कांग्रेस प्रवेश करने वालों में प्रमुख रूप से भेंसराम पंकज, जीतू पंकज, साहेब लाल यादव, मोहन लाल पंकज, मेघनाथ साहू, भागवत साहू आदि शामिल हैं। उक्त अवसर पर सोनाखान क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नल कुमार पटेल, सरपंच अश्वनी श्यामलाल साहू, पूर्व सरपंच संतोष कुमार साहू, पूर्व सरपंच लक्ष्मीन मानिकपुरी, पूर्व सरपंच पुनीतदास मानिकपुरी, मनोज साहू, कुंदन यादव, राजकुमार साहू, साहेब लाल साहू, भागवत साहू, कुशल साहू, बैजनाथ साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी संदीप अग्रवाल, भरत मेश्राम, दीपांजलि बारिक, प्रमोद साहू, छोटेलाल मानिकपुरी, जयंत यादव, ओम चौहान, पिंटू चौहान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

पैरी-महानदी का सीना चीर शासन को चुनौती दे रहे रेत माफिया

गरियाबंद। जिले में पैरी और महानदी के 8 अवैध घाट में 14 चेन माउंटेन से चौबीसो घंटे धड़ल्ले से रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। इस इलाके में हथखोज का एक खदान भर माइनिंग से अधिकृत है लेकिन यहा पैरी के सिंधोरी, महानदी के पिताईबंद, चौबेबांधा, परसदा जोशी में 9 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं जहां 14 चेन माउंटेन मशीन लगाई गई हैं। इन मशीनों से रोजाना अवैध रेत खनन चल रहा है। अंदरूनी इलाके के छोटी बस्तियों से निकलकर रेत से भरे हाईवा को ड्राइवर नेशनल हाइवे में दौड़ते हुए रायपुर भिलाई जैसे महानगरों तक बगैर किसी वैध दस्तावेज के ले जा रहे हैं। इसके एवज में खदान संचालक 4500 से लेकर 7800 रुपए तक वसूल रहे है। रोजाना 400 से 500 ट्रिप हाईवा रेत निकाला जा रहा है। दबाव बना या दुर्घटना हुई तो कार्रवाई दिखाने 7-8 हाईवा की जब्ती दिखाकर माइनिंग विभाग खाना पूर्ति कर देता है। धमतरी जिले से भी ज्यादा रेत परिवहन अब गरियाबंद से होने लगा है।

राजस्व के कुछ अफसर ईमानदारी से कार्रवाई भी करने फील्ड में उतरते हैं तो उन पर सिंडीकेट द्वारा राजनीति पावर के बूते नकेल कस दिया जाता है। एक वायरल विडियो में रेत घाट के सिंडीकेट के पीछे सत्ताधारी संगठन के जनप्रतिनिधियों का नाम तक गिनाया जा रहा है। मौजुदा स्थिति और बिना रोक टोक के चल रहे खदान इस रेत के सिंडीकेट को राजनीतिक सरंक्षण की पुष्टि भी करते हैं।

कवरेज के लिए गए तो होगी पिटाई

सिंडीकेट ने अपनी करतूत ढकने के लिए गुर्गे भी फैला रखे हैं। घाट के आने-जाने वाले रास्तों में कई नकाबपोश दिखेंगे। बीते 1 मई को सिंधोरी घाट में हो रहे अवैध निकासी का विडियो बनाने पहुंचे राजिम के यूट्यूब नागेंद्र निषाद की पिटाई कर दी गई, जिसका विडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित के शिकायत के बाद राजिम पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए मारपीट का मामल दर्ज किया है। नागेंद्र ने बताया कि उसके मोबाइल पर कॉलर ने उनसे कहा कि वह एसपी ऑफिस से बात कर रहा है और जिसके खिलाफ शिकायत किया गया था वो लोग अब तुम्हारे खिलाफ एट्रोसिटी लगा रहे हैं, हालाकि कॉलर के बोलने के तरीके से नागेंद्र भी समझ गया कि उसे डराया जा रहा है।

विधानसभा में गूंजा था 80 हजार घनमीटर रेत चोरी का मामला

पूरे अवैध खनन में माइनिंग और एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। परसदा जोशी के पंचायत ने 30 जनवरी 2021 में महानदी को बचाने रेत खदान आवंटित नहीं करने का प्रस्ताव भी पारित किया था, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के मौन स्वीकृति में परसदा जोशी इलाके में 4 घाटों पर रेट खनन चल रहा है। सबसे ज्यादा मशीनें भी इसी पंचायत के घाटों में हैं। बताया जाता है कि सभी घाट में प्रभावशाली राजनीति की एंट्री है, लिहाजा सबसे सुरक्षित इसी खदान को माना जाता है जहां कार्रवाई करने के लिए अफसरों को सोचना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक रोजाना इस घाट से 225 से 250 ट्रिप तक रेत की निकासी होती है। पिछले वित्तीय वर्ष में महानदी के 9.80 हेक्टयर रकबे में हुए 80 हजार घन मीटर रेत चोरी का मामला विधायक धरम लाल कौशिक ने फरवरी में संपन्न हुए सत्र में उठाया था।

राजिम, रेत और राजनीति

'राजिम, रेत और राजनीति' यह तुकबंदी भी वर्तमान हालत पर सटीक बैठती है। जिस दल के पास राजनीति पावर है उसी दल के लोगो का सीधा कनेक्शन घाट से होता है। इनके नाते रिश्तेदार के अलावा कई नाम सिंडिकेट में आ रहे हैं। कांग्रेस के सत्ता काल में जो कांग्रेस का दामन थाम कर रेत की राजनीति में घुसे थे, उनमें से कुछ नामचीनों ने अब भाजपा में शामिल होकर रेत की राजनीति का नवीनीकरण करवा लिया है। पैसे बटोरने के चक्कर में नदियों का हाल बद से बदतर हो गया है। रेड जोन में शामिल पैरी नदी के सिंधोरी घाट में अब 10 से 12 फिट गहरे खुदे नजर आ रहे हैं। यही हाल महानदी के घाटों का भी है।

खदान में माइनिंग कर्मियों की पिटाई

सिंधोरी घाट में हो रहे अवैध निकासी का विडियो बनाने पहुंचे राजिम के यूट्यूब नागेंद्र निषाद की पिटाई के मामले में जब गरियाबंद के जिला खनिज अधिकारी फगुलाल नागेश से बात की तो उन्होंने कहा कि मारपीट की घटना हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर वहां अवैध तरीके से घाट चलाया जा रहा होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। रेत परिवहन में लगे 16 वाहन को जब्त भी किया गया है जिसमें 14 राजिम तो 2 वाहनों को फिंगेश्वर थाना के सुपुर्द किया गया है।

कितने बाहरी और कितने स्थानीय को दिया रोजगार, 7 दिन के भीतर दें जानकारी

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने सार्वजनिक उपक्रमों को लिखा पत्र

रायपुर। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कोरबा जिले के सभी सार्वजनिक उपक्रमों सहित निजी प्रतिष्ठान को पत्र लिखकर बाहरी और स्थानीय श्रमिकों की जानकारी 7 दिवस के भीतर तलब की है. एसईसीएल के कोरबा, गेवरा, दीपका मुख्य महाप्रबंधक, बालको, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मंत्री देवांगन ने पत्र लिखा है.

मंत्री लखन लाल देवांगन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि स्थानीय बेरोजगारों के माध्यम से आए दिन शिकायतें आ रही है की स्थानीय बेरोजगारों की बजाय बाहरी लोगों की भर्ती की जा रही है. जबकि स्थानीय लोगों को 70 फीसदी लेना है और बाहरी लोगों को 30 फीसदी लेना है. वर्तमान में सार्वजनिक

उपक्रमों में नियोजित कई ठेका कंपनियों द्वारा स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा की जा रही है. जो की अनुचित है. मंत्री देवांगन ने सभी उपकर्मों से 7 दिन के भीतर स्थानीय और बाहरी श्रमिको की जानकारी मांगी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार की मंशा भी स्थानीय लोगों को काम पर रखने की है.

डाटा से स्थिति होगी स्पष्ट, बेरोजगारों को मिलेगा काम

पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित निजी कंपनियों में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, श्रमिक स्थानीय हैं या फिर बाहरी हैं, इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में ठोस पहल नहीं हो पाती थी. निजी ठेका कंपनियों द्वारा मनमानी की जाती थी, अब श्रमिकों की वास्तविक जानकारी सामने आने के बाद बेहतर प्रयास संभव हो सकेगा. उद्योग मंत्री देवांगन स्थानीय बेरोजगारों के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रहे हैं.

संदिग्ध हालत में पकड़े गए 21 युवक-युवतियां

बिलासपुर में चल रहा था देह व्यापार का गंदा धंधा

बिलासपुर। शहर के पॉश कॉलोनियों में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एजेंट कोलकाता से कॉल गर्ल बुलाकर पॉश कॉलोनियों आसमां सिटी फेस.2, अमेरी स्थित सांई अपार्टमेंट, गोकुल धाम में किराये के मकानों में देह व्यापार करा रहे थे। 5 महिला समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन सीएसपी और प्रशिक्षु आईपीएस उमेश कुमार ने शिकायत के बाद छापेमारी की।

सकरी के आसमां सिटी फेस.2 और गोकुल धाम पार्क के मकान में देह व्यापार की शिकायत मिली थी। पुलिस ने जब छापेमारी की तो युवक और युवतियां संदिग्ध हालत में पकड़े गए। मौके से 65,830 रुपए कैशए 26 मोबाइल, आपत्तिजनक वस्तुएं, शराब की बोतलें, बाइक, ब्लैंक चेक, दो कार और बाइक बरामद किये गये हैं।

पुलिस की टीम ने अमेरी स्थित साई विहार अपार्टमेंट में दबिश दी, तो वहां रुखसार अहमद उर्फ जावेद, नाजिर अंसारी और मधुमाला सिंह बर्मन मिले। जिनसे पूछताछ के बाद कमरे की तलाशी ली गई। कमरे में युवक-युवती संदिग्ध हालत में मिले। इस दौरान पूछताछ में उनके दो और ठिकानों की जानकारी मिली।

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि शहर में सैक्स रैकेट चलाने वाली महिलाएं और एजेंट कोलकाता सहित दूसरे राज्यों से कॉल गर्ल बुलाते थे। यहां किराए के मकान के अलग-अलग कमरों में ग्राहकों को बुलाकर युवतियों से देह व्यापार कराते थे। इसके बदले में ग्राहकों से मोटी रकम वसूली करते थे वहीं, कॉल गर्ल को भी मन-मुताबिक पैसे देते थे। पुलिस ने लड़कियों को दैहिक शोषण के व्यापार से मुक्त कराने का दावा किया है। साथ ही कोलकाता की 4 युवतियों को रेस्क्यू कर पुनर्वास के लिए कार्रवाई करने की बात कही है। बताया जा रहा है किए आसमां सिटी फेस.2 और अमेरी के सांई अपार्टमेंट में देह व्यापाहर का अवैध कारोबार पिछले लंबे समय से चल रहा था। इससे पहले भी पुलिस को स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी। लेकिन पुलिस दिखावे की कार्रवाई करती रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार चल रहा था। जिस पर पहली बार कार्रवाई की गई है।

हरा सोना समेटने में जुटे जिले के एक लाख संग्राहक

महासमुन्द। जिले के वनांचल में निवासरत करीब 1,07,885 ग्रामीणों की आजीविका का बड़ा जरिया तेंदूपत्ता संग्रहण एक मई से जिले में शुरू हो गया है। इसके साथ ही जंगलों में चहल. पहल भी बढ़ गई है। जिले में कुल 785 फड़ों में इस हरे सोने का संग्रहण किया जाता है। पहले दिन 90 प्रतिशत फड़ों में संग्रहण का काम शुरू हुआ है। 75 समितियों के माध्यम से जिले में तेंदूपत्तों का संग्रहण किया जाता है। इस दफे इसका लक्ष्य 91,300 मानक बोरा रखा गया है। गत वर्ष लगभग इतने ही तेंदूपत्तों का संग्रहण किया गया था। बताया गया है कि 2-3 दिन तेंदूपत्ता तोड़ाई की जाएगी। तत्पश्चात सप्ताह भर विराम दिया जाता है। ताकि तोड़ाई के बाद बचे कोमल और छोटे-छोटे पत्तों का विकास हो जाए। उसके बाद फिर से तोड़ाई की जाती है। इस तरह 3-4 बार सप्ताह भर का विराम देकर करीब माह भर इन पत्तों की तोड़ाइ की जाती है। तोड़ाई व संग्रहण के दौरान पहले दिन उप वन प्रबंध संचालक महासमुंद ए. आर. बंजारे ने दौरा कर जंगल में तोड़ाई और फड़ों पर संग्रहण कार्यों का निरीक्षण किया। हर वर्ष की तरह इस बार भी तोड़ाई पूर्व विभिन्न प्रकार की तैयारी की गई थी। संग्राहकों का सर्वे किया गया था। जिसमें एक संग्राहक के परिवार में महिला.पुरुषों की जानकारी एकत्र की गई थी। इस दफे 107885 संग्राहक इस कार्य में जुट रहे हैं। इसके अलावा तोड़ाई और संग्रहण कार्य की मॉनिटरिंग के लिए सभी फड़ों पर बीट गार्ड, सचिवों की तैनाती की गई है। फड़ मुंशियों और तेंदुपत्ता समितियों के कर्मियों को उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है।

15 सौ रुपये प्रति मानक बोरा मजदूरी बढ़ी

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए यह खुशी की बात है कि प्रदेश में बनी नई सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण की मजदूरी दर में 1500 रुपयों की बढ़ोत्तरी कर इसे 5500 रूपए कर दिया है। इसके पूर्व यह दर 4000 रूपए थी। बागबाहरा और पिथौरा के जंगलों में अच्छी क्वालटी का तेंदूपत्ता मिलता है।

लगातार सूख रहे कोडार के साथ बढ़ रही है गर्मी की चुनौती

महासमुंद। भीषण गर्मी के कारण बड़े बांधों के साथ ही छोटे बांधों का भी जलस्तर घट गया है। कोडार बांध में 9.90 फीट ही पानी शेष है। कोडार बांध में पिछले वर्ष से डेढ़ फीट कम पानी है। केशवा जलाशय में भी 16 फ ीट ही पानी शेष रह गया है, जो क्षमता का 16 प्रतिशत ही है। पिछले वर्ष कोडार बांध में 15 अप्रैल को तालाबों में पानी भरने के लिए पानी छोड़ा गया था और 21 मई तक पानी दिया गया था। उसके बाद भी 10 फीट पानी शेष था। 2024 में तालाबों के लिए पानी ही नहीं छोड़ा गया है और जल स्तर घटकर 9.90 फीट पहुंच गया है। मई माह में स्थिति और बिगड़ सकती है।

बताया जा रहा है कि अभी रबी फ सल तैयार नहीं हुई है। रबी फसल के लिए भी पानी दिया जाना है। कोडार बांध में रबी फ सल के लिए पानी

छोड़ने के पूर्व 21 फीट पानी था, जो घटकर 9.90 पहुंच गया है। पूर्व में 70 से 80 तालाबों को भरने की योजना बनाई गई। पानी कम होने के कारण संशय की स्थिति बरकरार है। महासमुंद क्षेत्र में तीन लघु जलाशय हैं। इसमें से बेमचा बांध सूख चुका है। परसदा लघु बांध में चार फीट पानी है और बेलटुकरी को निस्तारी के लिए पानी दे दिया गया है। बांधों में पानी कम होने से वितरक नहरों में भी पानी नहीं चल रहा है। जिससे दिक्कत और बढ़ गई है। पानी बेहिसाब खर्च हो रहा है। बड़े जलाशयों और लघु जलाशयों से पानी छोड़ने को लेकर बेहतर प्रबंधन नजर नहीं आ रहा है। मानसून सीजन में कोडार बांध में 28 फीट पानी था। इसके बाद खरीफ सीजन और रबी सीजन में फसलों को पानी दिया गया। रबी फसल के लिए जनवरी माह से ही पानी चल रहा है। जिले के ज्यादातर किसान रबी सीजन में भी धान की फसल लेते हैं। इसमें पानी अधिक मात्रा में जरूरत होती है। रबी के लिए पानी छोड़ने के पूर्व 21 फीट पानी कोडार में था, लेकिन अब 9 फीट ही रह गया है। जबकि, कई जगह रबी की फसल तैयार नहीं हुई है। इधर, ज्यादातर लघु बांध फरवरी व मार्च महीने में ही सूख जाते हैं।

कोडार शाखा के एसडीओ जीपी पाटिल ने बताया कि इस बार कोडार में भी जलस्तर काफी कम है। निस्तारी व तालाबों के लिए पानी दिया जाएगा या नहीं, इस पर आगामी दिनों में बैठक लेकर चर्चा की जाएगी। ज्यादातर लघु जलाशय सूख गए हैं। इस बार स्टॉफऔर श्रमिक नहीं मिलने से भी परेशानी हो रही है। पानी छोड़ने पर व्यर्थ बह सकता है।

भीषण गर्मी में भी नहर में पानी छोड़ने पर अधिकांश पानी नहरें भी सोख लेती हैं। कई नहरों में लाइनिंग का कार्य नहीं हुआ है। मिट्टी होने से पानी सोख लेते हैं। इससे भी पर्याप्त पानी तालाबों तक नहीं पहुंच पाता है। कोडार की मुख्य नहर की लंबाई 47 किमी, वितरक नहर की लंबाई 79 किमी और लघु नहर की लंबाई 197 किमी है। केशवा जलाशय की मुख्य नहर की लंबाई 26.10 किमी व छोटी नहर 18 किमी है।

'छत्तीसगढ़ का मॉरीशस'

'गोल्डन आइलैंड बुका'

कोरबा। अगर आप के पास ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं है और आप वीकेंड पर परिवार के साथ एक छोटी और खूबसूरत ट्रिप चाहते हैं तो कोरबा के 'बुका जलविहार' की ट्रिप आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। यहां लेक के बीच तन कर खड़ी विशालकाय चट्टानों के बीच से जब आपकी बोट गुजरेगी न, सच कहते हैं बिल्कुल फिल्मी सीन रीक्रिएट हो जाएगा। यहां मीलों तक गहरा पानी है। जंगलों और पहाड़ों से घिरी बुका लेक में बोटिंग के दौरान आपको कई छोटे-बड़े टापू भी देखने को मिलेंगे। फिर यहां वॉटर स्पोर्ट्स, घुड़सवारी आदि का भी बंदोबस्त है और अगर आपने आसपास घूमने का मन बना लिया फिर तो यादें कमाल की इकट्ठा होंगी। आप सतरेंगा पिकनिक स्पॉट, तीन पहाड़ों के बीच में स्थित रानी झरना, और थोड़ा और घूमना चाहें तो मैनपाट भी जा सकते है। जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। फिलहाल आज बात 'जलविहार बुका' की।

बुका वॉटर फ्रंट, गोल्डन आइलैंड ऑफ बुका या बुका जलविहार, जिस भी नाम से पुकारें, एक छोटी ट्रिप के लिए खूबसूरत जगह है। यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। रायपुर से इसकी दूरी करीब 230 किमी और बिलासपुर से करीब 80 किमी है। बुका लेक कोरबा-अंबिकापुर मार्ग पर पड़ती है। यह कोरबा बांगो डैम का भाग है और चोरनई नदी में बना हुआ है। यहां चारों ओर बिखरे खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए बहुत से पर्यटक आते हैं खासकर न्यू ईयर पर या फिर परिवार के किसी खास मौके को यादगार बनाने के लिए।

बुका लेक पर देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारे

अगर आप जंगल और पहाड़ों के बीच और विशाल जलराशि के किनारे खड़े होकर उगते सूरज का दीदार करना चाहते हैं तो बुका लेक एक सुंदर-शांत जगह है। सूर्यास्त के नज़ारे देखने के लिए भी खासतौर पर लोग यहां आते हैं। न आपाधापी न कोलाहल, दिल को गहराई तक सुकून का एहसास कराने वाली ऐसी शांति शहर के इतने पास और कम खर्च में मिल पाना दुर्लभ है।

जब आप बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं तो उनके मनोरंजन की व्यवस्था होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वे तो शांति की तलाश में नहीं ही आए हैं। उन्हें चाहिए मौज-मस्ती। ऐसे में बच्चों के लिए यहां चिल्ड्रेंस प्ले एरिया है। साथ ही कुछ वॉटर स्पोर्ट्स और घुड़सवारी की भी व्यवस्था है।

मेन अट्रेक्शन है बोटिंग

बच्चे हों या बड़े, सबको बोटिंग में तो मज़ा आता ही है। यहां मोटरबोट, शिकारे सभी कुछ उपलब्ध हैं। गहरे पानी में दूर-दूर तक बोटिंग का लुत्फ उठाना और खासकर तनकर खड़ी विशालकाय चट्टानों और टापुओं के बीच से आपकी बोट का निकलना बहुत खुश और हैरान करता है। वरना नॉर्मली ऐसे दृश्य फिल्मों में ही दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कम खर्चीली ट्रिप है जो आपके परिवार को तरोताज़ा कर देगी।

ठहरने का है शानदार प्रबंध

जलविहार बुका को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया है। यहां लेक फ्रंट पर दो डबलबैड और अटैच्ड टॉयलेट वाले टैंट्स हैं जिनमें चार लोगों का परिवार या दोस्त आराम से रुक सकते है। इसके अलावा ग्लास हाउस और हसदेव हाउस भी हैं। एसी रूम भी हैं।

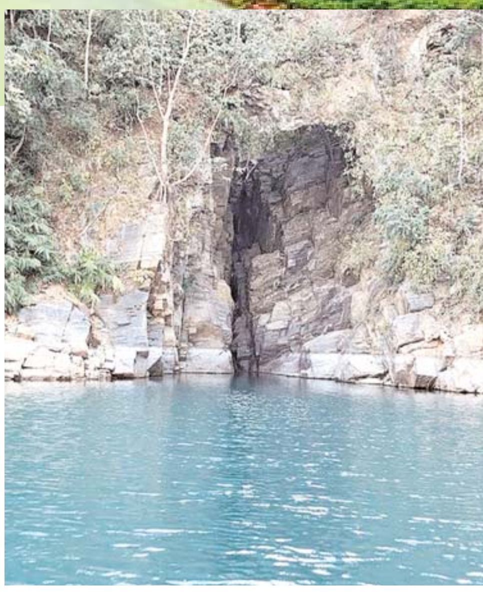

सभी की दर 15 सौ से लेकर छह हजार के आसपास है।

कैसे पहुँचे

अगर आप बाहर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं तो रायपुर एयरपोर्ट पर आ कर यहां से कोरबा के लिए कैब ले सकते हैं। नज़दीकी स्टेशन की बात करें तो कोरबा या जांजगीर-चाम्पा में रेलवे स्टेशन हैं। बिलासपुर स्टेशन पर भी आप उतर सकते हैं। सड़क मार्ग से यह पूरे छत्तीसगढ़ से अच्छी तरह जुड़ा है।

बुका लेक के आसपास घूमने की जगहें

बुका लेक के आसपास इन खूबसूरत जगहों पर भी आप घूम सकते हैं।

सतरेंगा पिकनिक स्पॉट

सतरेंगा पिकनिक स्पॉट छत्तीसगढ़ का एक बेहद खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यहां हरे-भरे पेड़ों और पहाड़ों के बीच पानी के किनारे समय बिताने का अपना अलग ही मज़ा है। सतरेंगा इसी डैम के दूसरे छोर में स्थित हैं। यहां फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग ब्रिज, टूरिस्ट कॉटेज और मोटर बोट की बेहतरीन सुविधा है। यहां फूड जोन में आपको चाइनीज़ , छत्तीसगढ़ी और साउथ इंडियन व्यंजनों की वैराइटी मिल जाएगी।

रानी झरना

ट्रैकिंग के शौकीन रानी झरना ज़रूर देखें। तीन पहाड़ों के बीच में स्थित रानी झरना तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। उसके बाद आप इस खूबसूरत जलप्रपात में पहुंच सकते हैं। रानी झरना कोरबा जिला मुख्यालय और सतरेंगा पिकनिक स्पॉट के बीच में स्थित हैं। इस झरने से 100 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई से बारहों महीने पानी गिरता है। लेकिन बारिश के दिनों में यहां जाना सुरक्षित नहीं है। रानी झरना के अलावा आप आसपास में केंदई वाटर फॉल और देवपहरी वाटर फॉल भी देख सकते हैं।

कोसगई दाई मंदिर

अगर आप देवी दर्शन के आकांक्षी हैं तो कोसगई माता मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। यह पहाड़ पर स्थित हैं। दरअसल कोसगाईगढ़ एक गांव है, जो फुटका पहाड़ के पहाड़ी इलाकों पर कोरबा-कटघोरा रोड से 25 किलोमीटर दूर है। यहां माता कोसगाई के मंदिर की बहुत महिमा है। दूर-दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। कोसागाईगढ़ में एक खूबसूरत किला है। इसका प्रवेश द्वार एक गुफा की भांति है और यह बहुत ही संकरा है। किले के चारों तरफ घना जंगल है, जिसमें भांति-भांति के जीव - जंतुओं को देखा जा सकता है। यहाँ आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी।

मंडी में किसानों को नहीं मिल रहा धान का समर्थन मूल्य

महासमुंद। पिटियाझर स्थित कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने खुली बोली के माध्यम से 600 कट्टा धान खरीदा। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पतला धान के लिए 2183 रूपए तथा मोटा धान के लिए 22 सौ रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। लेकिन, मंडी में कम व्यापारी आने की वजह से बोली द्वारा समर्थन मूल्य से कम में धान बिक रहा है। फलस्वरूप आगामी रबी की तैयारी के लिए किसान नुकसान सहकर अपनी उपज बेच रहे हैं। पिछले वर्ष 1932 से शुरू हुई बोली 1950 तक गई थी। इस बार पहले दिन 1931 से बोली शुरू हुई जो 1952 तक पहुंची। किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार तय एमएसपी से 342 बोली जानी है।

गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से कृषि उपज मंडी महासमुंद में खुली बोली के माध्यम से व्यापारियों द्वारा किसानों की धान खरीदी बंद थी जो केवल सौदा पत्रक के माध्यम से ही संचालित हो रही थी परंतु, पिछले साल किसान नेता एवं जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू

चंद्राकर द्वारा लगातार कोशिशों के कारण मंडी में धान खरीदी प्रारम्भ हुई है। जहां किसानों का धान न्यूनतम 1931 रूपए से अधिकतम 1952 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बिक्री हुआ। जागेश्वर जुगनू चंद्राकर ने किसानों से अपील की है कि सौदा पत्रक की बजाय ज्यादा से ज्यादा कृषि उपज मंडी प्रांगण में ही अपनी उपज बेचें। जिससे किसानों को मंडी के माध्यम से सुरक्षित भुगतान प्राप्त हो सके।

सबको जानकारी है कि साल 2017-18 में किसानों ने महासमुंद के एक राइस मिलर को सौदा पत्रक के माध्यम से सीधे तौर पर अपना धान बेचा था। लेकिन किसानों को उनके उपज का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। जिसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तब कहीं जाकर राइस मिलर की अचल संपत्ति नीलाम करने के पश्चात किसानों को भुगतान हो रहा है।

समर्थन मूल्य से 250 रु. कम में बिका धान

वर्षों से मंडी में बोली के माध्यम से खरीदी बंद थी। फलस्वरूप किसानों का धान औने पौने में व्यापारी खरीदते थे। लेकिन, पिछले 2 साल से रबी सीजन में किसानों का धान मंडी के द्वारा बोली लगाकर खरीदा जा रहा है। जिससे किसानों को सुविधा मिली है। हालाकि, पिछले 2 सालों में समर्थन मूल्य 250 रूपए कम में ही किसान अपनी उपज बेच रहे हैं।

पूर्व कांग्रेस विधायक की बहन-बहनोई और भांजे पर दहेज प्रताड़ना का आरोप

शराब-ड्रग के नशे में अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव

भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर की बहन, बहनोई और भांजे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ है। बहू मेघा बाघमार ने पति पर शराब और ड्रग के नशे में अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

पीड़िता के वकील गौरव शर्मा ने बताया कि पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर की सगी बहन मीना बाघमार और जीजा नरेश सहित भांजे सौम्य बाघमार के खिलाफ सेक्टर .6 भिलाई स्थित महिला थाने में 5 मई को दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज किया गया है।

बहू मेघा ने बताया कि उसकी शादी 27 जनवरी 2022 को शंकर नगर रायपुर निवासी सौम्य बाघमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद से ही पति और सास-ससुर उसे छोटी-छोटी बातों को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वो अपने ससुराल में मात्र 10 महीने ही रह पाई और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया।

इसके बाद वो अपने मायके मैत्रीनगर रिसाली भिलाई में रहने लगी। उसने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। मामले में काउंसिलिंग होने के बाद भी ससुराल वालों ने उसे रखने से मना कर दिया। फिर 4 अप्रैल को दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के पास कार्रवाई के लिए आवेदन दिया।

एसपी ने पूरे मामले की जांच कराई, तो पता चला कि उसका पति सौम्य बघमार छोटी-छोटी बात पर पत्नी मेघा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर पीटता था। कई बार उसे नशे की हालत में पति ने मारा और रुपए की मांग की। सास-ससुर ने घर से और दहेज लाने की बात पर उसे प्रताड़ित किया।

मेघा का आरोप है कि उसका पति सौम्य बाघमार शराब और ड्रग लेता था। शादी के करीब 6-7 दिन बाद ही

नशे में आया और अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। वो मोबाइल में एडल्ट फिल्म देखकर उसी तरह करने के लिए पत्नी पर दबाव बनाता था। जब मेघा ने इसका विरोध किया, तो उसने मारपीट की।

जब यह सिलसिला आए दिन का हो गया तो मेघा ने यह बात सास और ससुर को बताई। जिस पर पति ने फिर से उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट की। सास-ससुर ने कहा कि उनका बेटा जिस तरह रखेगा, तुमको उसी तरह रहना होगा।

मुख्यमंत्री के रिश्तेदार होने की देते थे धमकी

प्रतिमा चंद्राकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रिश्तेदार है। इसके चलते उसकी बहन और बहनोई मेघा के ससुराल वालों को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार होने की धमकी देते थे। मेघा ने बताया कि शादी के 10-15 दिन बाद ही उसके पति और सास ससुर फॉर्चूनर गाड़ी देने की बात को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे। उन्होंने कहा कि तेरे पिता और नाना ने गाड़ी देने को कहा, लेकिन नहीं दिए। हम मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। अगर अपने बेटे की शादी दूसरी जगह करते तो बड़ा दहेज मिलता। इसके बाद उन्होंने 20 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी लाने की बात कहते हुए मेघा को घर से निकाल दिया।

पीड़िता के वकील गौरव शर्मा ने बताया कि एक साल पहले जब ससुराल वालों ने मेघा बाघमार को मारपीट कर घर से निकाल दिया, तो उसने दुर्ग कोर्ट में धारा 9 के तहत आवेदन लगाकर गुहार लगाई कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। उस पर जबरन तलाक का दबाव बनाया जा रहा है।

इसके बाद उसके घर महिला आयोग की अध्यक्ष और पूर्व महापौर किरणमयी नायक, पूर्व महापौर आरएन वर्मा सहित कुछ अन्य लोग पहुंचे थे। उन्होंने मेघा और उसके परिवार वालों को काफी डराया धमकाया था। उसने इसकी शिकायत नेवई थाने में दर्ज कराई थी।

मेघा बाघमार ने बताया कि शिकायत के बाद दुर्ग पुलिस पर इतना राजनीतिक दबाव आया कि एक साल तक भटकने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ तो पीड़िता ने दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला को आवेदन दिया। इसके बाद महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है।

सुपेबेड़ा की विधवा माताओं का दर्द

गरियाबंद। जिले में किडनी पीड़ितों के गांव कहे जाने वाले सुपेबेड़ा के दर्द से अब कोई अनजान नहीं है। पिछले 17 सालों में यहां 130 से ज्यादा किडनी रोगियों की मौत हो गई और 2 दर्जन लोग अब भी बीमार हैं। राहत और बचाव के सरकारी दावे के बीच विधवा हो चुकी माताएं भी हैं जो अब बीमारी से नहीं व्यवस्था से जूझ रही हैं।

पति के गुजर जाने के बाद संवार रही हैं बच्चों का भविष्य

देवभोग के मनरेगा दफ्तर में फाइलों को संजो रहीं वैदेही और लक्ष्मी बाई, दोनों उसी सुपेबेड़ा ग्राम के है, जहां किडनी रोग काल बन कर आया। दोनों के पति शिक्षक थे लेकिन किडनी रोग से लक्ष्मी सोनवानी के पति क्षितिराम की मौत 2014 में तो वैदेही क्षेत्रपाल के पति प्रदीप की मौत 2017 में हो गई। बीमारी से ग्रसित पति को जमीन, जेवर तक बेचना पड़ा,

हाउस लोन निकाल कर इलाज में खर्च किए पर जान नहीं बचा पाई। दोनों के 3-3 संतान हैं। गुजर बसर और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। 2019 में राज्यपाल के दौरा के बाद इन्हें कलेक्टर दर पर प्रतिमाह 10 हजार पगार पर नौकरी मिल गई, लेकिन ये रुपये महंगाई के जमाने में गुजर बसर के लिए काफी नहीं है। इन्हें आज भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मदद की आस है।

किडनी की बीमारी से मुखिया के गुजर जाने के बाद गांव में और भी 80 से ज्यादा ऐसी बेवा हैं जो परिवार चलाने बिना किसी सरकारी मदद के संघर्ष कर रही हैं। सिलाई मशीन पर बैठ कर धागा पिरोती महिला प्रेम सिला के पति प्रीतम आडील के अलावा परिवार के सास-ससुर की मौत 7 साल पहले एक-एक करके बीमारी से हुई। छोटी ननद और दो बच्चे के भरण पोषण का जिम्मा अब प्रेम सिला के कंधे पर है। घर की हालत बता रही है कि सिलाई मशीन के भरोसे किसी तरह भोजन का इंतजाम कर पा रही है। गांव की गोमती बाई हो या रीना आडील, यशोदा हो या हेम बाई, सभी मजदूरी के भरोसे परिवार चला रही हैं।

सरकार के निर्देश के बावजूद जिला पंचायत ने केवल महिला समूह का गठन कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। पिछले 6 साल में 6 सिलाई मशीन देकर सारे महिलाओ के दर्द निवारण का दावा करने वाले जिला पंचायत के अफसर कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, इधर स्वास्थ्य विभाग के अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कह रहे हैं।

दो करोड़ रुपये का धान खरीदी घोटाला ...

सोसायटी प्रबंधक की जमानत याचिका हाईकोर्ट से निरस्त

बसना। पिथौरा विखं के जिला सहकारी बैंक मर्यादित बैंक शाखा पिरदा अंतर्गत सहकारी समिति जाड़ामुड़ा खरीदी केंद्र में फर्जी तरीके से 2 करोड़ रूपए की धान खरीदी मामले में किसानों की ऋण पुस्तिका देखे बिना पंजीयन रकबा में रकबा जोड़कर धान खरीदकर अनुचित लाभ अर्जित कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले तत्कालीन प्रबंधक उमेश कुमार भोई के जमानत याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तत्कालीन समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई द्वारा धान खरीदी सीजन 2023-24 में किसानों के खाते का मनमर्जी तरीके से रकबा बढ़ाकर जमकर फर्जीवाड़ा करते हुए अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने की शिकायत उनके खिलाफ थाना बसना में जनवरी 2024 को भादवि की धारा 420, 120 बी, 467, 471, 568, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध है। गिरफ्तारी से बचने उमेश कुमार भोई इस समय फरारी काट रहा है। इसी बीच उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की थी।

उमेश कुमार भोई के वकील ने उसे गिरफ्तारी से बचाने बिलासपुर हाईकोर्ट में दिए अपने दलील में उमेश भोई को बेगुनाह और तहसीलदार और किसानों को गुनहगार बताकर अग्रिम जमानत याचिका लगाकर उमेश भोई की जमानत की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दलील को यह कहकर खारिज कर दिया, क्योंकि उमेश कुमार भोई द्वारा किये गये फर्जीवाड़े से शासन को करीब 2 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है। डिप्टी कलेक्टर की टीम के साथ इस पूरे मामले की जांच की गई जिसमें समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई दोषी पाया गया।

नशे का नेटवर्क ध्वस्त करने पुलिस ने बनाई रणनीति

ड्रग्स के 150 ग्राहकों की सूची तैयार, शहर के नामी होटलों को जारी होगा नोटिस

रायपुर। राजधानी में एमडीएमए, कोकीन ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आते ही हड़कंप मच गया है। शहर में सिंथेटिक नशे के नेटवर्क को तोड़ने पुलिस की जांच और तेज हो चुकी है। एमडीएमए और कोकीन ड्रग्स तस्करी के मुख्य सरगना आयुष अग्रवाल सहयोगी महिला, अंतरराज्यीय आरोपी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस को उन ग्राहकों की तलाश है, जो इन तस्करों से ड्रग्स खरीदा करते थे।

शहर के कई ऐसे ग्राहकों की कुंडली पुलिस ने तैयार की है, जो आयुष अग्रवाल समेत अन्य तस्करों के संपर्क में थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आयुष अग्रवाल अपने ग्राहकों का ब्रॉडकास्ट ग्रुप तैयार कर उन तक ड्रग्स की कीमत और वेराइटी पहुंचाता था। शहर के बड़े होटलों से लेकर वीक एन्ड में होने वाली टेक्नो और आफ्टर पार्टीज तक ड्रग्स सप्लाई के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस और क्राइम ब्रांच की विशेष टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

शहर के नामी होटलों को जारी होगा नोटिस

शहर के दर्जनभर बड़े नामी होटलों की कुंडली क्राइम ब्रांच ने तैयार की है, जिन्हें जल्द नोटिस जारी कर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जायेंगी। शहर के होटलों और वहां होने वाली बड़ी टेक्नो-बॉलीवुड पार्टियों की जानकारी ली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक होटल शैमरॉक, होटल बुटीक एरिना, सायाजी, कोर्टयार्ड, होटल शीतल इंटरनेशन, होटल क्लार्क्स इन, होटल ग्रैंड इंपेरिया समेत कई होटलों को जल्द पुलिस का नोटिस जारी होगा। इस नोटिस के जरिए ग्राहकों की जानकारी पुलिस जुटाने वाली है। होटलों में ग्राहकों को किस तरह के रूम बुक होते हैं, इनमें किन आईडी का उपयोग किया जाता है, होटल के रूम बुकिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं, ग्राहक किन कारणों से रूम की बुकिंग रख रहे हैं, इस दौरान उनकी गतिविधि किस तरह की है, होटल में होने वाली आफ्टर पार्टीज में किस तरह के लोग पहुंच रहे हैं, जैसे ड्रग्स तस्करी से जुड़े कई अहम सुराग पुलिस के हाथों लगेंगे।

इस नेक्सेस के अंतिम ग्राहक तक पुलिस के हाथ जल्द पहुंच रहे हैं। ड्रग्स तस्करों के मोबाइल फोन से कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, तस्करों के संपर्क में 150 से अधिक ग्राहक जुड़े हुए थे। इनमें ज्यादातर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर जैसे शहरों के ग्राहक हैं। इतना ही नहीं आयुष एवं उसके सहयोगियों के बैंक विवरण से भी कई नाम सामने आए हैं, जिनका ज्यादातर आयुष अग्रवाल के खातों पर ट्रांजेक्शन होता था। सूत्रों के मुताबिक, आयुष अग्रवाल शहर के कई बड़े कारोबारियों के संपर्क में भी था, जिन्हें पुलिस जल्द पूछताछ के लिए तलब करने वाली है।

ड्रग्स के पूरे नेटवर्क का होगा सफाया- संदीप मित्तल

रायपुर क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी संदीप मित्तल ड्रग्स तस्करी के पूरे मामले को खुद लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी एंगल पर पूरी जांच चल रही है। शहर के होटलों में होने वाली टेक्नो पार्टीज, उसके बाद आफ्टर पार्टीज पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। इन पार्टियों में होने वाली हर एक गतिविधियों पर विशेष निगरानी है। होटलों को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी जाएगी। नारकोटिक्स विंग की स्पेशल टीम को एक्टिव किया गया है। इस नेक्सेस के अंतिम छोर तक जल्द क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी। शहर के कुरियर कंपनी, दूसरे राज्यों से आने वाली बस एवं अन्य गाड़ियो में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

ड्रग्स तस्करी का इंटरनेशनल नेटवर्क!

ड्रग्स तस्करी में नाइजीरियन गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस को शंका है कि दिल्ली से ड्रग्स की सप्लाई करने वाले महेश के संपर्क में नाइजीरियन गिरोह है, जो सीधे विदेश से ड्रग्स को भारत में खपाते हैं। इन मामले में आयुष और महेश से बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप से क्लू सामने आया है। जल्द पुलिस टीम अन्य राज्यों के लिए रवाना होने वाली है।

ड्रग्स सप्लाई में आयुष अग्रवाल का गिरोह नेटफ्लिक्स की सिरीज मनी हाईस्ट की तरह तरीका अपनाता था। सभी का नाम फिल्मी अंदाज में रखकर ठीक उसी तरह आयुष के गिरोह के लोग भी अनोखे अंदाज में ड्रग्स सप्लाई करते थे। शहर के ग्राहकों का व्हाट्सएप ग्रुप और ब्रॉडकास्ट बनाकर पहले ड्रग्स का ऑर्डर लिया जाता था, फिर ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद पैडलर ग्राहक के लाइव लोकेशन से कुछ दूर किसी दूसरे स्थान पर ड्रग्स को सुरक्षित छोड़कर निकल जाता था। ग्राहक को फोन कर उस जगह से ड्रग्स लेने की जानकारी देता था, ताकि पैडलर की पहचान ग्राहक के सामने उजागर न हो।

अब जनता खुद चुनेगी महापौर और नगर अध्यक्ष

बड़े बदलाव की तैयारी में लगी विष्णु सरकार

रायपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम के चुनाव के नियमों में बड़ा फेरबदल किया था। पूर्व में जहाँ निकायों में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता था और जनता इन शीर्ष पदों के लिए मतदान करती थी तो वही तत्कालीन भूपेश सरकार ने अध्यक्ष और महापौर के चुनाव का अधिकार चुने हुए पार्षदों को दे दिया था। इस नियम के बाद बहुमत के आधार पर चुनाव किया जाता था। तब की विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। राजनीति से दूर आम लोगों के बीच भी यह चर्चा थी कि इस तरह के नियमों से चुनावी गड़बड़ी और खरीद.फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा।

अब प्रदेश में सरकार बदल चुकी हैं लिहाजा यह भी तय हैं कि नई सरकार पुरानी सरकार के इस फैसले को पलटते हुए अध्यक्ष और महापौर के चुनाव का अधिकार आम मतदाताओं को वापस कर देगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि उनकी सरकार इस बारे में विचार कर रही हैं और लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद इस पर विचार.विमर्श कर फैसला लिया जाएगा।

अरुण साव ने यह भी बताया हैं कि वे नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इस साल के आखिर में जब नगरीय निकायों के चुनाव होंगे तो मतदाता एक बार फिर से एक के बजाये दो वोट कर पाएंगे। इनमे एक पार्षद तो दूसरा नगर अध्यक्ष का होगा।

अवैध कब्जे पर भंवरपुर में फिर चला बुलडोजर

बसना। ग्राम भंवरपुर में अवैध अतिक्रमण पर लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। 14 मई को रानी तालाब सड़क के किनारे अतिक्रमण कर घर ठेला लगाकर झुग्गी झोपड़ी बनाकर साग-सब्जी, मछली सहित अन्य वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले 16 कब्जाधारियों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया। वहीं, फिर एक बार शुक्रवार को भंवरपुर के अटल चौक के पास प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए 20-25 वर्षों से घर, पान, ठेला मोबाइल दुकान बनाकर काबिज छः लोगों के अवैध कब्जों को हटाया गया।

इस दौरान प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। प्रशासन पर व्यक्ति विशेष के फायदे के कारण अतिक्रमण की कार्रवाई करने आरोप लगाया गया। इस दौरान भंवरपुर मुख्य मार्ग पर लगभग 6 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। शासकीय भूमि सड़क मद की भूमि में अतिक्रमणकर्ता अजय पिता अर्जुन द्वारा पान ठेला, गुलाल पिता उत्तम सिंह द्वारा मकान, मंजूलाल पिता रोधन द्वारा पान ठेला तथा शासकीय भूमि पडाव मद की भूमि में अतिक्रमणकर्ता विजय पिता राममनोहर द्वारा मकान, सालिकराम पिता पुरन द्वारा मकान नारायण पिता मोहन द्वारा मकान, मोबाइल दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिसे बेदखल किये जाने हेतु 13 मई को न्यायालय नायब तहसीलदार भंवरपुर द्वारा बेदखली वारंट जारी किया गया। किंतु, अतिक्रमणकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

अन्ततः राजस्व, पंचायत और पुलिस विभाग की टीम 17 मई को अतिक्रमण हटाने पहुंची। जहां कब्जाधारियों को समझाइश दी गयी। लेकिन, ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार नोक-झोंक के बीच पुलिस चौकी भंवरपुर के सहयोग से राजस्व विभाग और पंचायत द्वारा बुलडोजर चलाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस दौरान अपरान्ह लगभग 11 बजे से शाम 04 बजे तक भंवरपुर मुख्य सड़क मार्ग में जाम की स्थिति बनी रही।

213 गांवों में घर तक नहीं पहुंचा शुद्ध पेयजल

जल जीवन मिशन योजना की कछुआ गति

सरायपाली। जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना का लाभ ब्लॉक के 237 गांव में से 213 गांव के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। मात्र 24 गांव के ग्रामीण ही लाभान्वित हो रहे हैं। शेष गांव में कहीं टंकी तो कहीं पाइप लाइन, नल कनेक्शन देने का कार्य अधूरा है। इस तरह कुल मिलाकर जल जीवन मिशन का लाभ मात्र 16 प्रतिशत ग्रामीण ही ले रहे हैं। बता दें कि सरायपाली ब्लॉक के 237 गांवों में जल जीवन मिशन योजना स्वीकृत हुई है। इसमें से एकमात्र भीखापाली पंचायत को छोड़ शेष 236 गांव में जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, दरअसल, भीखापाली में पूर्व में जिस कांट्रेक्टर ने काम लिया था वह काम पूरा नहीं कर पाया, इसके चलते उसका एग्रीमेंट निरस्त कर फिर से टेंडर किया गया है, जिसके चलते वह गांव में अभी तक जल जीवन मिशन का काम प्रारंभ नहीं हो पाया है।

ज्ञातव्य है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत स्वीकृत हुए 237 गांव में से मात्र 24 गांव में योजना का लाभ ग्रामीण शत प्रतिशत उठा रहे हैं। शेष गांव में कार्य प्रगति पर है। सरायपाली ब्लॉक में कई गांव में जल जीवन मिशन योजना का कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन नलकूप के अभाव में पानी टंकी व घरों में दिए गए नल कनेक्शन शो पीस बनकर रह गए हैं। इस तरह की स्थिति में जहां जल स्तर काफी नीचे चला गया है वहां देखा जा सकता है। पहले से नल-जल योजना जहां संचालित हैं वहां रेट्रोफिटिंग के तहत 51 गांवों में जल जीवन मिशन योजना का कार्य स्वीकृत हुआ है, जबकि 186 गांव में सिंगल विलेज के तहत जल जीवन मिशन योजना स्वीकृत हुई है, कुल 237 जल जीवन मिशन योजना ग्रामों में से 236 गांव में ही कार्य प्रारंभ हुआ है। 13 गांवों में रेट्रो फिटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और 38 गांवों में कार्य प्रगति पर है। इसी तरह 11 गांवों में सिंगल विलेज का कार्य पूर्ण है तथा 174 गांवों में प्रगति पर है।

जल जीवन मिशन योजना के तहत दो तरह के कार्य स्वीकृत हुए हैं एक तो पहले से ही नल जल योजना संचालित है, वहां रेट्रो फिटिंग के तहत राशि स्वीकृत हुई है, उक्त गांव में कांट्रेक्टर द्वारा यह देखा जाएगा कि नल-जल योजना के तहत पाइप लाइन का विस्तार सभी मोहल्ले में हुआ है या नहीं। जिस मोहल्ले में पाइप लाइन विस्तार नहीं हुआ है, तो विस्तार करने जिनके घरों में नल कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन देने, जहां टंकी निर्माण नहीं हुआ तो टंकी निर्माण करने अलग-अलग तरह के कार्य के लिए अलग-अलग राशि स्वीकृत हुई है।

लगाई जाएगी पेनाल्टी: साहू

पीएचई विभाग के एसडीओ खिलेश्वर साहू ने कहा कि 24 गांवों में जल जीवन मिशन योजना का लाभ पूर्ण रूप से ग्रामीण ले रहे हैं, शेष गांव में प्रगति पर है, कांट्रेक्टर निर्धारित समय पर जल जीवन मिशन योजना का कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों पर की जाने वाले कार्रवाई के बारे में बताया कि समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर उन्हें पेनाल्टी लगेगी। इसके अलावा जहां जलस्तर काफी नीचे चला गया है वहां नलकूप खनन में समस्या आ रही है। उन्होंने लंबित सभी जल जीवन मिशन योजना के कार्य में तेजी आने का संकेत दिया।

राशि स्वीकृति के बाद भी कालेज भवनों का निर्माण लटका

महासमुंद। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज को खुद का भवन नसीब नहीं हो पाया है। जबकि, एक साल पहले ही भवन निर्माझा के लिए 12 करोड़ रूपए की स्वीकृति मिली थी। प्राक्कलन बनाकर लोक निर्माण विभाग को भेजा गया था, लेकिन भवन निर्माण का अता-पता नहीं है। वर्तमान में वल्लभाचार्य कॉलेज के वाणिज्य भवन में आत्मानंद कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत मचेवा में शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य कॉलेज के सामने हेलीपेड वाली भूमि का चिन्हांकन भी किया गया था। अंग्रेजी मीडियम कॉलेज में पहले सत्र की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। अब दूसरे सत्र में भी नए छात्र पढ़ने के लिए आएंगे। ऐसे में कक्षाओं के संचालन में समस्या आ सकती है। कॉलेज में छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी। अंग्रेजी मीडियम कॉलेज में छात्र पढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं। शासकीय आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज में भी बीएससी, बीकॉम और बीए की कुल 240 सीटें है। पिछले वर्ष बी कॉम में सबसे ज्यादा छात्रों ने प्रवेश लिया था। जैसे-जैसे छात्राओं की संख्या में वृद्धि होगी, कक्षाओं के संचालन को लेकर समस्या बढ़ेगी।

ज्ञातव्य है कि पिछले साल पूरे प्रदेश में 10 अंग्रेजी मीडियम कॉलेज खुले थे। इसमें महासमुंद में एक कॉलेज खुला था, लेकिन भवन को लेकर अब आचार संहिता समाप्त होने का इंतजार है। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। अंग्रेजी मीडियम कॉलेज की प्राचार्य अनुसुइया अग्रवाल ने बताया कि भवन निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग को प्राक्कलन बनाकर भेजा गया था। मचेवा में ही कॉलेज का भवन बनाया जाना है। इसी प्रकार कोमाखान में भी कॉलेज किराए के भवन में चल रहा है। कॉलेज के स्वयं के भवन बनने का इंतजार है। शासकीय नवीन महाविद्यालय चिरको का भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। चिरको कॉलेज भी किराए के भवन में संचालित हो रहा है। रंगमंच और ग्राम पंचायत के पुराने भवन में कक्षाएं लगाई जा रही है। रंगमंच और ग्राम पंचायत के पुराने भवन में कक्षाएं लगाई जा रही है।

सूने मकान से 5 लाख के आभूषण चोरी

बसना। समीपस्थ ग्राम खेमड़ा में चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर 5 लाख रूपए के जेवरात की चोरी को अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी श्रीकांत साहू पिता पृथ्वीराज साहू 39 वर्ष निवासी सोनी कॉलोनी खेमड़ा जो पीएचसी भंवरपुर में आरएमओ हैं, 22 मई 2024 को अपरान्ह 11 बजे घर में ताला लगाकर ड्यूटी चले गए। जबकि, उसके घर के बाकी सदस्य झगरेनडीह रिश्तेदार के घर गए थे। शाम लगभग 6 बजे श्रीकांत घर वापस आये और बाहर स्टील गेट दरवाजा खोलकर अंदर गये तो देखा कि घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी तथा ताला जमीन पर पड़ा था। घर के बेडरूम की आलमारी का लॉक टूटा हुआ था तथा आलमारी के अंदर रखा सामान बिखरा हुआ था। जिसे चेक करने पर आलमारी में रखा 1 नग सोने का रानी हार कीमती करीबन 2.74 लाख, 1 नग सोने का हार सामान्य कीमती 1.30 लाख, 3 जोड़ी सोने के कान का टॉप्स कीमती 40 हजार, 3 जोड़ी चांदी की पायल कीमती 14 हजार, 5 नग सोने का लॉकिट कीमती 30 हजार, तथा चांदी की कटोरी व चम्मच कीमती 2 हजार रूपए, कुल 4 लाख 90 हजार रूपए के जेवर नहीं थे।

आजादी के 70 साल बाद भी नही मिली सड़क सुविधा

विकास की किरण से बंचित हैं चेरूडिपा के ग्रामीण

10 किमी घूमकर जाने की मजबूरी

बसना। ब्लॉक मुख्यालय का आदिवासी बहुल ग्राम चेरूडिपा आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस वनांचल ग्राम में 35 आदिवासियों के परिवारों की संख्या ढाई सौ से अधिक है जिन्हें हर छोटी बड़ी तमाम प्रकार की समस्याओं से मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीण 7 दशक से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं परंतु, आज पर्यंत नसीब नहीं हुई है। जिससे शासन प्रशासन के प्रति रहवासियों में रोष व्याप्त है। बसना ब्लॉक मुख्यालय से 25 किमी दूर अंतिम छोर में बसा ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर जिससे संबद्ध वनांचल ग्राम चेरूडिपा में समस्याओं का अंबार है। समस्याएं भी छोटी-मोटी नहीं लगातार कोशिशों के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की उदासीनता, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और गांव की मजबूरी इस कदर हावी है कि गांव तक पहुंचने के लिए एक मात्र सड़क कच्ची है।

आजादी के बाद पिछले 7 दशक से यहां के ग्रामीण पक्की सड़क की आस लगाए बैठे है। लेकिन, उन्हें ये आज तक नसीब नहीं हुई है। चेरूडीपा गांव के एतवारू नागवंशी, पांडव, समारू सहित आधा दर्जन ग्रामीणों ने बताया कि भंवरपुर बड़े साजापाली मुख्य सड़क मार्ग से चेरूडीपा महज 3 से 4 किमी है। बरसात के दिनों में गांव का संपर्क आसपास के गांवों से पूरी तरह से टूट जाता है। न कोई इस गांव में आ सकता है न यहां से कहीं और जा सकता है। बरसात के दिनों में इस कच्ची सड़क पर गड्ढे बन जाते हैं और रास्ता दल-दल में तब्दील हो जाता है। फिसलन के चलते लोग गिरते-पड़ते रहते हैं। पुरुष हो या महिला बरसात के चार महीने गुजारना उनके लिए भारी मुसीबत भरा होता है। जहां लोगों को पैदल चलने में परेशानी होती है, उसी रास्ते से यहां के विद्यार्थी माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने जमदरहा और भंवरपुर जाते हैं।

उक्त आदिवासी बहुल ग्राम के लोगों को पंचायत मुख्यालय जाने में भी कठिनाई है। चेरूडिपा से पंचायत मुख्यालय पुरुषोत्तम पुर की दूरी महज 2 किमी है लेकिन, वहां जाने के लिए कोई सुविधायुक्त मार्ग नहीं है। इन दिनों गर्मी में लोग खेत के मेड़ों के सहारे आना-जाना करते हैं जबकि, बरसात में तो यह पूरी तरह बंद हो जाता है।

चेरूडीपा के ग्रामीण पेयजल और निस्तारी की समस्या से भी वर्षों से जूझ रहे हैं। साल दर साल पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है। जल स्त्रोत के साधन डबरी तालाब फरवरी माह में ही सूख जाता है। एक बोर और एक हैंडपंप में ग्रामीणों द्वारा स्वयं के खर्चे से मोटर पंप लगाया गया है। जिसमें भी रूक-रूक पानी आता है तथा गर्मी में जवाब देने लगता है। पूरा गांव गर्मी में एक हैंडपंप के सहारे अपनी प्यास बुझा पाता है। यदि बिजली कट जाए तो लोग कुएं के दूषित पानी का उपयोग करने विवश हैं। निस्तारी के लिए जमदरहा गांव जाना पड़ता है।

गर्मियों में जानलेवा हो सकता है डायरिया

गम्भीर स्थिति होने से पूर्व ही लें डॉक्टर की मदद

गर्मियों में तापमान बढ़ते ही डायरिया के मामलों में भी तेजी आने लगती है। इससे बचने के लिए खानपान से लेकर हाइजीन तक कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

मई के महीने में तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने इंसानों के साथ ही पशु-पक्षियों की हालत भी खराब कर दी है। बढ़ते तापमान के बीच स्वस्थ रहना भी खुद में एक चुनौती होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जैसे-जैसे पारा बढ़ता है तो लू लगने, कालरा, डायरिया जैसी समस्याएं होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। डायरिया गर्मी के दिनों में होने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक है, लेकिन जरा सी लापरवाही आपकी सेहत के ऊपर भारी पड़ सकती है।

डायरिया होने पर उल्टी और दस्त की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

डायरिया की मुख्य वजह रोटावायरस माना जाता है। यह एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेट और आंतों में सूजन होने लगती है और इससे गंभीर दस्त की समस्या होने लगती है। स्ट्रीट फूड का सेवन करना, फ्रोजन फूड का ज्यादा सेवन, हाइजीन का ध्यान न रखना आदि के कारण से भी डायरिया हो सकता है,क्योंकि पैरासाइट, बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण की वजह से डायरिया का जोखिम बढ़ता है।

डायरिया से बचने के सामान्य तरीके

भरपूर मात्रा में पिएं पानी

डायरिया से बचाव के लिए जरूरी है कि भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें। इसके अलावा नारियल पानी, मौसमी फलों का सेवन, घर पर बना नीबू का शरबत, दही जैसी चीजों को भोजन में शामिल करें। इससे शरीर डिहाइड्रेट नहीं होता है और गट हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है।

साफ-सफाई का रखें खास ध्यान

डायरिया से बचने के लिए साफसफाई का खास ध्यान रखें। बच्चों में खाने से पहले हाथ धोने की आदत डालें। बाहर की चीजें खाने से बचना चाहिए। हमेशा फिल्टर किया हुआ या फिर उबालकर पानी पिएं।

इन चीजों का सेवन करने से बचें

पाचन खराब होने की वजह से दस्त की समस्या शुरू होती है जो डायरिया में बदल सकती है, इसलिए गर्मियों के दिनों में खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए। भोजन से ज्यादा मसालेदार और तला भुना खाना कम कर दें। इसके साथ ही खुद को ठंडा रखने के लिए बाहर का फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा, आइसक्रीम जैसी चीजें न खाएं। खासतौर पर जंक फूड के सेवन से बचें।

डायरिया के लक्षण दिखाई देने पर क्या खाएं

अगर आपको डायरिया से जुड़े लक्षण दिखाई दे रहे हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट में केला शामिल करना चाहिए। भारी खाने के स्थान पर खिचड़ी खाएं, क्योंकि ये सुपाच्य होती है। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए नींबू पानी, नारियल पानी, ओआरएस जैसी हेल्दी ड्रिंक्स पिएं।

रोगी की हालत गम्भीर न होने दें

डायरिया के कारण होने वाला डिहाइड्रेशन कुछ परिस्थितियों में जानलेवा हो सकता है अस्तु लापरवाही न बरतें तथा रोगी की गम्भीर स्थिति को देखते हुये निकटतम हॉस्पीटल में ले जायें।

गर्मियों में खानपान पर दें विशेष ध्यान

अनियमित जीवन शैली हो सकती है घातक

वर्तमन स्थिति में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग भी कुछ खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्य वर्द्धक समझ कर उनका लगातार सेवन करते जा रहे हैं जो सेहत के लिए बेहद घातक हैं।

हमारा भोजन और जीवन शैली इतनी खराब हो गई है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। भोजन का सम्बन्ध सिर्फ जीभ और स्वाद से रखते हैं। जो जुबान को भाता है वही खाते हैं। भोजन में पोषक तत्वों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग डाइट को लेकर सतर्क भी होते हैं और अपने हिसाब से प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्यप्रद भोजन सामग्री का सेवन करें। हेल्दी डाइट के नाम पर वे डाइट में ऐसी चीजों को भी खाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि जहर की तरह असर करती हैं।

ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत नाश्ते से करते हैं जिसमें वो ब्राउन ब्रेड का सेवन करते हैं। लोगों का मानना है कि ब्राउन ब्रेड सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। ब्राउन ब्रेड को सफेद ब्रेड की तुलना में काफी हेल्दी माना जाता है। आप जानते हैं कि जिस ब्राउन ब्रेड को आप आटा की ब्रेड समझकर खा रहे हैं वो असल में रिफाइंड वीट फ्लौर है यानि वो मैदा है।

कुछ भोज्य पदार्थ जैसे पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड, फैट फ्री प्रोडक्ट, एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन शेक और प्रोटीन बार जैसे फूड्स में ना सिर्फ फ्रुटोज और मैदा मौजूद होता है बल्कि इसमें फैट बढ़ाने वाले तत्व भी मौजूद होते हैं। आप रोजाना हेल्दी फूड्स के नाम पर जहर का सेवन कर रहे हैं।

खराब भोजन ही हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना रहा है। एक रिपोर्ट की मानें तो भारत में 56.4 फीसदी आबादी की खराब सेहत के लिए उनकी डाइट जिम्मेदार है। डाइट में अस्वास्थ्यकर सामग्री का सेवन आपको जाने अनजाने में ही बीमार बना रहा है। कम उम्र में लोगों में डायबिटीज, दिल की बीमारी, एनीमिया और कैंसर जैसी बीमारियां पनप रही हैं जिसके लिए खराब डाइट और बिगड़ती जीवनशैली जिम्मेदार है। आइए जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा भोजन और जीवनशैली कैसी होनी चाहिए।

स्वास्थ्यप्रद भोजन में करें इन चीजों को शामिल

- आप रोजाना प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अंडा और चिकन का सेवन करें। आप का सेवन करें। डाइट में दालों को शामिल करें आपको स्वस्थ प्रोटीन मिलेगा।
- आप रोजाना हरी सब्जियों का सेवन करें। सीजनल सब्जियों का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं।
- सैचुरेटेड फैट और चीनी का सेवन करने पर कंट्रोल करें। बहुत अधिक संतृप्त वसा का सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है जिससे दिल के रोगों का खतरा बढ़ सकता है।
- चीनी का सेवन कम करें। नियमित रूप से उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करने से मोटापे और दांतों की सड़न का खतरा बढ़ जाता है।
- खाने में नमक का सेवन करने पर कंट्रोल करें और वजन को कम करें। बढ़ता वजन कई बीमारियों का कारण बनता है।
- पानी का सेवन अधिक से अधिक करें।

डायबिटीज के रोगी मरीज आम खा सकते हैं

डॉ. स्वाति सिंह
डायटीशियन

सालभर के इंतजार के बाद फलों का राजा आम आता है। आम के प्रेमी गर्मियों में आम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन दिनों कई तरह के आम वाजार में मिलने लगे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आम का स्वाद पसंद आता है। मीठा, रसीला आम देखकर खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डायबिटीज के मरीज भी आम को देखकर ललचाने लगते हैं। ऐसा हो भी क्यों न, आम का स्वाद होता ही कुछ ऐसा है कि खाए बिना कोई नहीं रह सकता है। हालांकि डायबिटीज के मरीज आम खाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि आम की मिठास कही उनका शुगर लेवल हाई न कर दे। चलिए जानते हैं कि डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं या नहीं और एक दिन में कितने आम खा सकते हैं ?

कीटो डाइटिशियन डॉक्टर स्वाति सिंह के मुताबिक डायबिटीज के मरीज भी आम खा सकते है, लेकिन इसकी सीमित मात्रा ही भोजन में शामिल करें। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्वीकार्य स्तर का है, इसलिए शुगर के मरीज भी खा सकते हैं। जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होता है उन्हें डायबिटीज में खा सकते हैं। आम का जीआई करीब 51 होता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज भी आम खा सकते हैं।

डायबिटीज में आम खा सकते हैं

अगर आप डायबिटिक हैं और आम खाते हैं तो जान लें आम का लो ग्लाइसेमिक लोड होता है। मतलब जब आप आम खाते हैं तो इससे तुरंत शुगर लेवल हाई नहीं होता है। आम में बहुत अधिक फाइबर होता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। आम विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम जैसे मिनरल से भरपूर होता है। आम में एक बायोएक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसे मैंगीफेरेन कहा जाता है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कई स्टडीज में ये तो ये भी पाया गया है कि आम पीपी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है।

आरोपों-प्रत्यारोपों में ओझल सार्थक मुद्दे

शिवकांत शर्मा

चुनाव प्रचार के हाल के चरणों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुछ बयानों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तत्परता से वीडियो प्रतिक्रिया जारी की, उनसे आमने-सामने की खुली बहस के लिए उत्सुकता होना स्वाभाविक है। उन्होंने प्रधानमंत्री को टीवी पर सीधी बहस की चुनौती भी दी। आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच टीवी पर सीधी बहस की परंपरा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत लगभग हर बड़े लोकतंत्र में मौजूद है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अलावा राज्यों के गवर्नरों और सीनेटरों के चुनावों से पहले भी टीवी पर दो से तीन बहसें होती हैं, जिनका आयोजन तटस्थ आयोग द्वारा आमंत्रित नागरिकों के समक्ष कराया जाता है। राष्ट्रपति बाइडन और ट्रंप के बीच कड़वाहट की पराकाष्ठा के कारण पिछले राष्ट्रपति चुनाव में बात शटअप और तू-तड़ाक तक पहुंच जाने के बावजूद ये दोनों इस बार के चुनाव में भी दो टीवी बहसों के लिए तैयार हो गए हैं। भारत में अभी तक शीर्ष नेताओं के बीच टीवी पर सीधी बहस की परंपरा नहीं है। इसके अभाव में नेता अपनी जनसभाओं और मीडिया में एक-दूसरे के बयानों और घोषणा पत्रों के बिंदुओं को मनमुताबिक तोड़-मरोड़ कर पेश करते रहते हैं। ऊपर से इंटरनेट मीडिया पर बातों को मनमाना रंग देने से ऐसा भ्रमजाल बन जाता है, जिसमें मतदाता के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले पाना कठिन होता जा रहा है। इसलिए यदि चुनाव आयोग की देखरेख में शीर्ष नेताओं के बीच टीवी पर एक-दो सीधी बहसों के आयोजन की शुरुआत हो सके तो ज्वलंत मुद्दों पर पार्टियों और उनके नेताओं की सही राय, समाधान और उनकी व्यावहारिकता को समझने में मतदाता की सहायता हो सकती है।

भारत में सीधी टीवी बहसें कराने में दो व्यावहारिक समस्याएं आ सकती हैं। पार्टियों की बड़ी संख्या और बहस में अनुशासन बनाए रखना। पार्टियों की बड़ी संख्या का हल तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जनसमर्थन की न्यूनतम सीमा के आधार पर हो सकता है, ताकि तीन से चार उम्मीदवार ही बहस के योग्य साबित हों। इसके बावजूद अनुशासन बनाए रखना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि सदनों के भीतर नारेबाजी, प्लेकार्ड दिखाना और शोर-शराबा बड़ी आम बात हो चुकी हैं। इसलिए टीवी बहस में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि एंकर पूरी तरह तटस्थ हों। सवाल यह है कि सीधी टीवी बहस की सबसे बड़ी जरूरत किसे है? निश्चित रूप से विपक्ष को है। राहुल गांधी सीधी टीवी बहस द्वारा रेखांकित करना चाहते हैं कि वह राष्ट्रीय स्तर के नेता और पीएम पद के दावेदार हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीधी बहस में लाभ कम और जोखिम अधिक है, परंतु चुनाव मतदाता को करना है और यदि उसकी दृष्टि से देखें तो सीधी बहस उसकी कई भ्रांतियों को दूर करने और ऐसे सार्थक मुद्दों को चर्चा में लाने में सहायक हो सकती है, जो आरोपों-प्रत्यारोपों की आंधी में ओझल हो गए हैं।

जलवायु संपदा की रक्षा, आर्थिक संपदा के सृजन के लिए तेज विकास, रोजगार सृजन और शिक्षा में उद्योग और कारोबार की मांग के अनुरूप सुधार ऐसे विषय हैं जिन पर देश ही

नहीं पूरी दुनिया का भविष्य निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र जल संस्था की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गत दो दशकों के भीतर उत्तर भारत का 95 प्रतिशत भूजल निकाला जा चुका है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के बड़े जलाशयों में उनकी पूरी क्षमता का एक चौथाई जल ही जमा हो रहा है। दक्षिण भारत के जलाशयों की स्थिति सबसे चिंताजनक है। नदियों का जल स्तर घट रहा है और बढ़ते विकास एवं शहरीकरण के कारण पानी की मांग निरंतर बढ़ रही है। किसी शहर के नल का पानी साफ किए बिना पीने लायक नहीं बचा है। भारत दुनिया की वायु प्रदूषण राजधानी बन चुका है। विश्व के 30 में से 21 सबसे प्रदूषित शहर भारत में हैं। जलवायु की इस घातक स्थिति की रोकथाम करते हुए उद्योगीकरण और आर्थिक विकास की गति बढ़ाना देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बिना लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। उनका जीवन स्तर नहीं सुधर सकता और शिक्षा में मूलभूत सुधार किए बिना इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता, परंतु क्या चुनाव प्रचार में इनमें से किसी भी चुनौती पर गंभीर विचार हुआ है? मीडिया अध्ययन संस्थान यानी सीएमएस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावों में इस बार 1.35 लाख करोड़ रुपये खर्च होने जा रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? कौन दे रहा है? कोई चर्चा है? एक पक्ष संविधान बदल देंगे, कहकर डरा रहा है तो दूसरा आपकी संपत्ति अल्पसंख्यकों में बांट देंगे कहकर।

जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया अमेरिका, यूरोप और जापान के चुनावों के समय आर्थिक नीतियों, पर्यावरण नीतियों और भूराजनीति पर होने वाली बयानबाजी पर कान लगाए रहता है, वही भारत के चुनाव में उनकी कोई चर्चा न होने पर परेशान नहीं होता। जबकि पश्चिम के सारे हित सीधे तौर पर इससे जुड़े हैं कि भारत की आने वाली सरकार कैसी जलवायु नीति, आर्थिक नीति और भूराजनीति अपनाती है और कितनी स्थिर रह पाती है। पूर्व में स्ट्रेट टाइम्स से लेकर पश्चिम में लास एंजलिस टाइम्स तक लगभग हर अखबार और उनसे जुड़े चैनलों की चिंता तानाशाही, बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकों और असंतुष्टों की दबती आवाज को लेकर है। प्रतिरोध की आवाज दबाए जाने की तो चिंता है, लेकिन पार्टियों के भीतर बढ़ती कुनबाशाही और तानाशाही को लेकर कोई चिंता नहीं।

तथ्यों और आंकड़ों से लैस एंकरों द्वारा संचालित सीधी टीवी बहस सच और झूठ की भी कुछ गुत्थियां खोल सकती हैं। लोक लुभावन वादे करने वाले नेताओं से पूछा जा सकता है कि जो वे बांटना चाहते हैं, उसके लिए धन कहां से आएगा? लोगों की गाढ़ी कमाई से एकत्र राजस्व को बांटना अधिक लाभकारी होगा या बुनियादी विकास में निवेश करना? अल्प संख्यकों के हितों को सर्वोपरि रखना सांप्रदायिक नहीं है तो फिर बहुसंख्यकों के हितों और चिंताओं की बात करना कैसे सांप्रदायिक है? जब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था अस्थायी मानी गई है तो उसकी उपादेयता पर विचार करना कैसे संविधान, विरुद्ध है? सीधी बहस में ऐसे कुछ असहज करने वाले प्रश्नों के साथ-साथ राजनीतिक चंदे और दलगत लोकतंत्र के ऐसे सवालों पर भी चर्चा हो सकती है, जिनसे हर पार्टी बचकर भागना चाहती है।

पांच वर्षों में रोकी गई 33 नाबालिगों की शादी

सामाजिक कुरीति और वैधानिक अपराध है बाल विवाह

हो सकता है एक लाख रूपये अर्थदण्ड सहित दो वर्ष का कारावास

महासमुंद। अब बाल विवाह कराया तो आपको 2 साल की कारावास हो सकता है। अब तक महिला बाल विकास का बाल विवाह रोका दस्ता केवल समझाइश देता आया है लेकिन, अब बाल विवाह के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार हर साल अक्षय तृतीया मुहुर्त में सैकड़ों शादियों के बीच उनके परिजन नाबालिग बालक, बालिकाओं की भी शादी करा देते हैं। हालाकि, बाल विवाह के विरुद्ध महिला बाल विकास, पुलिस तथा प्रशासन की संयुक्त टीम समय समय पर संबंधित घरों में पहुंचकर बाल विवाह को रोकती आई है तथा परिजनों को समझाइश देकर बालिग होने तक तिथि को आगे बढ़ती रही है।

महासमुंद जिले में 5 वर्षों से कुल 33 बाल विवाह रोके गए। इनमें से ज्यादातर वर-वधुओं को बालिग होने के लिए 1 माह से 6 माह की अवधि शेष थी। अब शासन के निर्देश पर बाल विवाह के विरुद्ध एक अभियान चलाकर कार्य किया जा रहा है। फलस्वरूप अब पहली बार पकड़ाने पर टीम द्वारा समझाइश दी जाएगी। फिर भी यदि, परिजन बाल विवाह कराते हैं तो उनके विरुद्ध एक लाख रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बेटियों का संरक्षण ही अभियान की प्राथमिकता

बाल विवाह मुक्त अभियान चलाने के सबसे बड़ा मकसद है, बेटियों के भविष्य को बचाना। जिले के आदिवासी बहुल इलाके में आज भी बड़े पैमाने पर छोटी उम्र में बेटियों का विवाह कर दिया जाता है। कम उम्र में विवाह करने से लड़कियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कम उम्र में मां बनने के दौरान बेटियों की मौत और नवजात की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता है। सरकार ये चाहती है कि कम उम्र में होने वाली शादियों के इन दुष्प्रभावों से बेटियों को बचाया जाए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 20-24 आयु वर्ग की 23.3 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई। जच्चा-बच्चा मृत्युदर रोकने विभाग अब अभियान की पहल कर रहा है।

बाल विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी होगी कार्रवाई

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे - संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात विवाह को स्वीकार नहीं करते तो बालिग होने के पश्चात विवाह को शून्य घोषित करने आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। हम सभी का दायित्व है कि समाज में व्याप्त इस बुराई को रोकें।

इस महत्वकांक्षी अभियान का संचालन महिला बाल विकास विभाग के नेतृत्व में किया जाएगा। सरकार को मदद देने के लिए यूनिसेफ सहयोग करेगी। जिलों में बाल विवाह के चौकाने वाले आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। सरकार की इस योजना से बाल विवाह पर प्रतिबंध तो लगेगा ही साथ ही साथ लोग जागरूक भी होंगे।

बुलेट पर भारी पड़ा बैलेट

नक्सली धमकी के बाद भी हुआ बिंद्रानवागढ़ में 81.19 प्रतिशत मतदान

गरियाबंद। न धौंस चली न धमकी काम आई, प्रदेशभर में सर्वाधिक मतदान 81.19 प्रतिशत बिंद्रानवागढ़ में हुआ। कई गांवों में मतदान बहिष्कार का एलान फिर भारी नक्सली गतिविधियों की चुनौती के बावजूद सफल और सर्वाधिक मतदान कराने में प्रशासन सफल रहा। जिला प्रशासन की कुशल रणनीति और बेहतर समन्वय के चलते सफल ही नहीं बल्कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान कराने वाले विधानसभा में नाम दर्ज हो गया। जिले में कुल 81.19 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें राजिम में 75.59 तो बिंद्रानवागढ़ में 81.19 प्रतिशत मतदान हुआ।

उदंती अभ्यारण के भीतर बसे कोयबा, साहेबिन कछार, इंदागांव व गरीबा पंचायत ने मतदान के सप्ताहभर पहले चुनाव बहिष्कार का एलान कर प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। जब पूरे इलाके में मतदान केंद्रों में चहल पहल थी तो वही कोयबा के दो मतदान केंद्र नागेश, साहेबिन कछार, कोदोमाली व गरीबा मतदान केंद्र में सन्नाटा पसरा रहा। दिन चढ़ते जा रहा था प्रशासन में खलबली मची हुई थी। सुबह 10 बजे इन क्षेत्रों के प्रतिनिधि व ग्रामीणों के

साथ चर्चा करने उन्हें बम्हनी झोला बुलाया गया। एसडीएम तुलसीदास मरकाम, एसडीओपी बाजीलाल के साथ कई अफसरों ने ग्रामीणों से चर्चा शुरू की।

शुरुआती 2 घंटे की चर्चा में ग्रामीणों का तेवर कम नहीं हुआ। समस्याओं से घिरे ग्रामीणों के ज्यादातर सवालों के उत्तर अफसरों के पास नहीं थे। बात बनने के बजाए बिगड़ती जा रही थी। इस बैठक की पल पल की सूचना जिला प्रशासन ले रहा था। ऐसे में मोर्चा संभाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले चर्चा करने पहुंचे। पहले उन्होंने सब की बातें सुनी फिर अपनी बात अपने अंदाज में रखना शुरू किया। कांबले कड़क मिजाज के साथ ही शांत तरीके से ठोस पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने ग्रामीणों के हर सवाल का एक जवाब देकर शांत करा दिया। लगभग 45 मिनट चली चर्चा में कांबले ने ग्रामीणों की समस्यायें नोट करके कहा कि सभी को आपने आजमाया, अब आपकी समस्या के साथ पुलिस खड़ी रहेगी।

उन्होंने आमामोरा रोड में 20 साल से रुकी पड़ी पक्की सड़क का उदाहरण देते हुए कहा कि बहिष्कार इसका हल नहीं है। एसएसपी की चर्चा का असर भी हुआ। गरीबा, साहेबिन, कोदोमाली, नागेश में वोटिंग एक बजे से शुरू हो गई क्योंकि यहां 3 बजे तक मतदान होना था। इसी तरह कोयबा के दोनों बूथों में दो बजे के बाद मतदाताओं की भीड़ देख अफसर भी गदगद हो गए।

अतिसंवेदनशील माने जाने वाले मतदान केंद्र ओढ़ में 79 प्रतिशत, आमामोरा में 63 प्रतिशत, गरीबा में 71 प्रतिशत, कमारभौदी में 83 प्रतिशत, बड़े गोबरा में 75.7 प्रतिशत, गौर गांव में 33.45 प्रतिशत, साहेबीन कछार में 12.5 प्रतिशत, कोदोमाली में 48 प्रतिशत, नागेश में 53 प्रतिशत मतदान हुआ, वहीं बहिष्कार करने वाले ग्राम कोयबा में 63 प्रतिशत, मतदान कर मतदाताओं ने निडरता का परिचय दिया है। चुनाव से पहले अमलीपदर थाना क्षेत्र के कई गांव में नक्सली धमकी व वोट डालने पर उंगली काटने की धमकी की खबर निकलकर आ रही थी। इस धमकी के बावजूद अंदरूनी इलाके में हुए मतदान प्रतिशत ने भय मुक्त मतदान का परिचय दे दिया है।

तैनात थी 20 अतिरिक्त कंपनी

जिले में डटे फोर्स के अलावा बस्तर चुनाव खत्म होते ही गरियाबंद जिले में 20 अतिरिक्त कम्पनी तैनात की गई थी, जिसमे 15 सीआरपीआरएफ , 4 एमपीएसएफ, एक सीएएफ, जिन्हें नक्सली गतिविधि इलाके में तैनात कर भय मुक्त मतदान कराने का सफल प्रयास किया गया। संवेदनशील इलाके में दो दिन पहले से ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। अभ्यारण्य इलाके में मतदान दल को निकालने में भी पुलिस ने कारगर रणनीति अपनाई। प्रचलित मार्ग के बजाए पहले से प्लान में शामिल कम आवाजाही वाले मार्गों का चयन किया गया। आमामोरा ओढ़ में दल को लाने ले जाने सेना चौपर का इस्तेमाल किया गया।

बेरोजगारी भत्ता बंद होने के बाद कम हुआ युवाओं का आकर्षण

रोजगार कार्यालय से बेरोजगारों का मोह भंग

महासमुंद। बेरोजगारी भत्ता बंद होने के बाद से ही रोजगार कार्यालय व मार्गदर्शन केंद्र में आवेदन करने वालों की संख्या भी घट गई है। पूर्व की तुलना में आधे से भी कम आवेदन आ रहे हैं। एक बार फिर से पंजीयन कराने में युवा अब रूचि नहीं दिखा रहे हैं। जबकि, वे मोबाइल से खुद भी आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार कार्यालय और मार्गदर्शन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार जिले में जीवित पंजीयन की संख्या 61561 है। 2023 में जनवरी माह तक पंजीयन की संख्या 42 हजार थी। भत्ता मिलने के बाद से ही आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ गई थी। अप्रैल माह में अब तक 331 लोगों ने ही पंजीयन कराया है। प्रतिमाह दो से तीन हजार आवेदन आने लगे थे, लेकिन अब आवेदनों की संख्या घट गई है। जबकि, शासन द्वारा मोबाइल और च्वाइस सेंटर से भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है।

पहले भत्ते की आस में युवा बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे थे। प्रदेश में सरकार बदलते ही योजना ठंडे बस्ते में चली गई और हजारों युवाओं को निराशा हाथ लगी। इस साल जनवरी में 2510, फरवरी में 2555, मार्च में 1320 और अप्रैल में 331 आवेदन आए हैं। जबकि, अब मोबाइल से ही सारा कार्य हो जा रहा है। नवीनीकरण के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी एओ लॉरी ने बताया कि अब कार्यालय में आए बिना ही मोबाइल ऐप से पंजीयन किया जा सकता है। इस कारण कार्यालय में लोग पंजीयन कराने के लिए नहीं आ रहे हैं। घर बैठे ही कार्य हो रहा है। किसी माह कम, किसी माह ज्यादा आवेदन आते हैं।

बेरोजगार युवाओं को अब कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। विभाग द्वारा आवेदकों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ ई-रोजगार एप भी तैयार किया गया है। इसके माध्यम से आवेदक खुद मोबाइल से पंजीयन भी करा सकते हैं। मार्च महीने में ही लांच किया गया है, लेकिन इसके बाद भी आवेदन की संख्या घट गई है। अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए कार्यालय में भी नहीं जाना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में ऐप पर ही जॉब के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

ज्ञातव्य है कि जिले में 5616 युवा बेरोजगारी भत्ता के पात्र थे। नवंबर माह से ही भत्ता बंद हो गया है। रोजगार कार्यालय में अभी भी युवा जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं हालाकि, सरकार बदलते ही योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई है। भत्ता के लिए भी सात हजार से अधिक आवेदन आए थे।

12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की सीबीआई ने जांच

रायपुर। बेमेतरा जिले के बिरनपुर हत्याकांड की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। एक युवक की हत्या के मामले से संबंधित आरोपों पर सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त अनुरोध और आगे डीओपीटी भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर 12 आरोपियों के विरुद्ध 26 अप्रैल को फिर से मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर 12 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 एवं 120.बी के तहत, साजा पुलिस स्टेशन, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में पूर्व में दर्ज प्राथमिकी संख्या 87/2023, दिनांक 08-04-2023 की जांच को अपने हाथों में लिया है।

आरोप है कि एक गांव के कक्षा 07- 08 में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक समुदाय के लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी। यह भी आरोप है कि जब पीड़ित अपने दोस्तों के साथ दोपहर में उक्त समुदाय के क्षेत्र में गया, तो उस समुदाय के लोगों ने छत से पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित के सिर में चोटें आईं और वह नीचे गिर पड़ा। इसके बाद उक्त 12 आरोपियों एवं अन्य लोगों ने कथित तौर पर तेज चाकू, घातक हथियारों से पीड़ित की हत्या कर दी। अपनी जांच के दौरान स्थानीय पुलिस को प्राथमिकी में नामित उक्त 12 आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक सबूत मिले एवं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

बाद में स्थानीय पुलिस ने सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। वर्तमान में सभी आरोपपत्रित आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- गुलाब दास दीवान, द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित। RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक- गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139